● वर्ष-2
● अंक-178
रायपुर, शनिवार 18 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

600 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप

डा. रमन के सवाल पर सदन में जमकर हंगामा, दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज राशन घोटाले के आरोप पर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी नोंकझोंक के दौरान भाजपा सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर अध्यक्ष चरणदास महंत ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने इस मामले की जांच विधायकों की समिति से कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की। जिसके जवाब में कांग्रेस सदस्यों ने भी नान घोटाले को लेकर नारेबाजी की। इस टकराव के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से सवाल किया कि क्या शासन ने राशन दुकानों में आगामी दो माह के, शत प्रतिशत अनाज, शक्कर आवंटन संबंधी नियम बनाया है, यदि हां, तो कब से प्रचलन में है? उन्होंने लगातार दो माह शत प्रतिशत अनाज, शक्कर आवंटन देने के बाद, तीसरे महीने, बीते दो महीनों में, वितरण के बाद बचे अनाज और शक्कर की मात्रा को घटाकर, तीसरे महीने शेष आवंटन देने के प्रावधान के बारे में पूछा। डॉ. रमन सिंह के सवाल पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ऐसा नियम नहीं बनाया गया है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर डॉ. रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए राशन दुकानों में भंडारण को लेकर गरीबों के राशन में गोलमाल का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, कृष्णमूर्ति बांधी, सौरभ सिंह, रंजना साहू, रजनीश सिंह, धर्मजीत सिंह ने विधायकों की समिति से जांच कराने की मांग की। मंत्री द्वारा विपक्ष की मांग स्वीकार न करने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।

विधायक डॉ. रमन सिंह पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के तहत राशन दुकानों में भेजे गए चावल, शक्कर, गुड़, चना और नमक के स्टॉक की बचत हो जाए तो उसे विभाग को बताना होता था। इस सरकार ने उक्त आदेश को ताक पर रखते हुए राशन दुकानों को बिना पिछले माह के बचत का मिलान किए हर महीने स्टॉक भेजते रहे। डॉ. सिंह बताया कि जब विभाग ने राशन दुकानों के स्टॉक और विभाग के वेबसाइट में इंट्री में मिलान किया तो चावल के स्टॉक में 68,930 मीट्रिक टन का अंतर पाया गया। इसी तरह शक्कर के स्टॉक में प्रदेश के सभी राशन दुकानों में भेजी गई मात्रा और जिले के दर्ज मात्रा में 3,359 मीट्रिक टन शक्कर का अंतर पाया गया है। ऐसा ही हजारों मीट्रिक की मात्रा का अंतर नमक, चना और गुड़ के स्टॉक में भी पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गरीबों के राशन की उच्च स्तर पर कालाबाजारी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 200 क्विंटल क्षमता वाले राशन दुकानों के गोदाम में 500 क्विंटल से अधिक चावल रखा गया है। उन्होंने यह बताया कि यह जानकारी संचालनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी द्वारा 13 दिसंबर 2022 को भेजे गए समस्त कलेक्ट्ररों को भेजे गए पत्र से भी स्पष्ट होता है। उन्होंने इस पूरे मामलें में 600 करोड़ रु. के घोटाले का आरोप लगाया है। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है। ऐसे मामलों की जांच जारी है और कई अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई भी की गई है। मंत्री ने बताया कि बड़ी संख्या में राशन दुकानों के लायसेंस भी रद्द किए गए हैं। सदन में उठे मामले की जानकारी दी और बताया इस मामले की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने कहा।

चिटफंड पर जमकर भिड़ंत, भाजपा का स्थगन प्रस्ताव खारिज

विधानसभा के शून्यकाल के दौरान चिटफंड घोटाले की राशि की वापसी को लेकर हंगामे के बाद भाजपा का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा सदस्यों ने छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों से जनता की रकम वापस देने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में उसका स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर सदन में चर्चा कराई जाए। भाजपा सदस्यों ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा होना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी ने चिटफंड कंपनियों से जनता की रकम वापस लौटाने का वादा किया था। कुछ राशि लौटाई गई है लेकिन उसके विज्ञापन में बड़ी रकम खर्च की गई। विपक्ष ने कहा कि अकेले सहारा कम्पनी में जनता का 3 हजार करोड़ रुपये फंसा हुआ है। जनता को चिटफंड कंपनियों में फंसी राशि देने का वादा जन घोषणा पत्र में किया गया था। कहा जा रहा है कि चिटफंड कंपनियों की जमीन नीलाम करके जनता को रकम लौटा रहे हैं। विपक्ष ने इसमें भी तौर तरीके को लेकर आपत्ति जताई। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखे। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से टोके जाने पर भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने शून्यकाल में मंत्रियों के खड़े होने पर ऐतराज किया।

इन दिनों

✍ राजेश बादल

पिछलग्गू बनने पर मजबूर क्षेत्रीय दल?

देश में कुछ समय से छोटी और मंझोली राजनीतिक पार्टियों ने लोकतंत्र में अपना महत्व साबित किया है। सबूत के तौर पर कुछ दशकों में संपन्न विधानसभा चुनाव परिणाम हैं। इनसे स्पष्ट है कि जब स्थापित राष्ट्रीय दल मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो स्थानीय नेतृत्व को भी अवसर देने से अवाम नहीं झिझकती। यह अलग बात है कि नए उभरे राजनीतिक दल भी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने के नजरिये से बहुत कामयाब नहीं रहे हैं। उनमें संगठन के चुनाव समय पर नहीं होते और उनके संस्थापक अध्यक्ष सारी उमर पार्टी के चौधरी बने रहते हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी में उनकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं खड़के। जब वे नहीं रहते तो उनके परिवार को संगठन-सत्ता मिल जाती है। इन स्थितियों में लोकतांत्रिक कर्तव्य और मतदाताओं की सेवा हाशिये पर चली जाती है। सामंती सोच नई-नवेली पार्टी पर हावी हो जाती है। नए निजाम समझते हैं कि मतदाता को उसके दर पर आना चाहिए, उसे मतदाता के पास जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी और राष्ट्रीय पार्टियां अगर लोकतंत्र में विस्तार करने के लिए आजाद हैं तो छोटे, प्रादेशिक और क्षेत्रीय दलों का रास्ता भी किसी ने नहीं रोका है।सवाल यह है कि इन प्रादेशिक पार्टियों ने क्या अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है? व्यावहारिक धरातल पर इसका उत्तर तनिक निराश करने वाला है। इसे समझने के लिए लगभग तीन दशक पहले जाना होगा, जब हिंदुस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर आया था। मतदाता बड़ी पार्टियों के कामकाज से निराश हो चला था और वह सियासत में नए क्षत्रपों को प्रवेश की अनुमति देने का मन बना चुका था। मंझोले दलों ने आगाज तो बेहतरीन अंदाज में किया, लेकिन बाद में उनके आंतरिक लोकतंत्र की गाड़ी पटरी से उतर गई। लोकहित के मुद्दे शुरुआत में उनकी पार्टी की प्राथमिकता सूची में रहे, मगर बाद में समूचा दल पार्टी नेतृत्व की झोली में चला गया और व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हो गए। परिणाम यह हुआ कि यह क्षेत्रीय दल विस्तार नहीं कर सके। वे अपने-अपने राज्य के प्रतिनिधि दल तो बन गए, पर राज्य की सीमाओं से आगे जाकर अपना आकार नहीं बढ़ा सके। लोकतंत्र को इसका नुकसान यह हुआ कि जो मतदाता बड़ी पार्टियों के विकल्प के रूप में इन दलों को आजमाना चाहता था, वह निराश हो गया। इन दलों ने अपना राष्ट्रीय संस्करण लोगों के सामने नहीं रखा। उन्होंने अन्य प्रदेशों में जाकर लोकतंत्र की ताजी हवा की खिड़की नहीं खोली और खुद को बड़ी पार्टियों की पिछलग्गू बना लिया। या तो वे एक गठबंधन में शामिल हुए या फिर उसके प्रतिद्वंद्वी गठबंधन में।

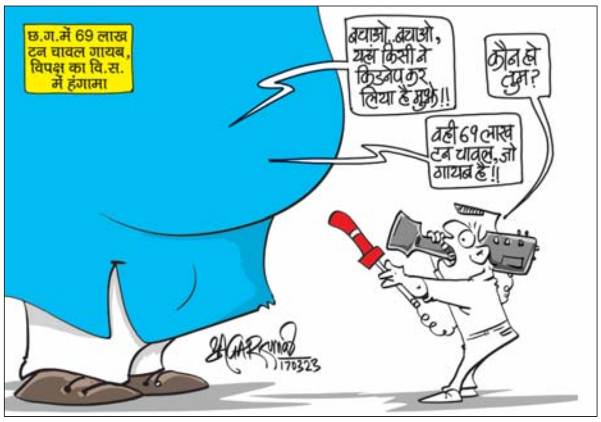

सबके रास्ते अलग, लेकिन मंजिल एक-संघ प्रमुख

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (त्र्स्स्) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि पूजा-पद्धति किसी धर्म का एक अंग होता है। यह किसी धर्म का संपूर्ण सत्य नहीं होता है। अंतिम सत्य हर धर्म का मूल होता है और सबको उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको अपना रास्ता सही दिखाई पड़ता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक सत्य को ही प्राप्त करना होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को इकबाल दुर्रानी द्वारा अनुवादित सामवेद के हिंदी-उर्दू संस्करण का लोकार्पण करते हुए कहा कि सनातन धर्म में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के

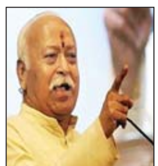

ज्ञान के बिना ज्ञान को पूर्ण नहीं माना जाता है। वेद सूत्र वाक्य की तरह होते हैं, उनके संपूर्ण अर्थ को समझने के लिए उपनिषद जैसी अन्य रचनाओं की आवश्यकता होती है। हमें इनका अध्ययन करना चाहिए जिससे हम उनके मूल संदेशों को समझ सकें।

उन्होंने एक धार्मिक प्रसंग के सहारे कहा कि अलग-अलग रूप से उपासना करने के बाद भी सुखी रहा जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सबकी उपासना का आदर करते हुए सत्य की उपासना करनी चाहिए। यही अंतिम ज्ञान का स्वरूप है।

औरंगजेब हार गया, मोदी जीत गए

डॉ. इकबाल दुर्रानी ने कहा कि दाराशिकोह को वेदों का अनुवाद करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ कारणों से वे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आज उन्होंने दाराशिकोह का वह अधूरा काम पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य में बाधा बनने वाला औरंगजेब आज हार गया और मोदी जीत गए क्योंकि उनके कार्यकाल में आज वह स्वप्न पूरा हो गया।

उन्होंने कहा कि सामवेद सार्वकालिक सत्य है, यह रूहानी संदेश है जिसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। वे चाहते हैं कि सामवेद को मदरसों-स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए और इस पुस्तक को शिक्षा संस्थानों में प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वे इसके लिए हर राज्य में जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग अकारण एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ऐसे में सामवेद के प्रेम संदेश और शाश्वत सत्य को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह महिलाओं के रंग अलग-अलग होते है, लेकिन उन सबके दूध का रंग सफेद होता है, उसी तरह सनातन सबका मूल है और इसे समझने-अपनाने की आवश्यकता है।

प्रमुख समाचार

चौतरफा फंसे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर उठ रहे सवाल

नई दिल्ली। लंदन में अपने लोकतंत्र की मृत्यु टिप्पणी पर राहुल गांधी की माफी के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद के साथ इस मुद्दे ने बजट सत्र को बाधित कर दिया है और विशेष संसदीय समिति की जांच की मांग करने वाले भाजपा के साथ आगे बढ़ने की संभावना है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी को यूके की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने माफी मांगने लायक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। थरूर ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि लोकसभा में बोलने से पहले राहुल गांधी संसद के बाहर माफी मांगें। यह दुख की बात है कि एक परिवार का अहंकार संसद की संस्था से ऊपर है... अगर वह संसद के प्रति गंभीर हैं, तो उन्हें संसद का सहारा लेने से पहले तुरंत बाहर माफी मांगनी चाहिए थी।

टीएमसी-सपा ने लोकसभा चुनाव से पहले गैर-कांग्रेस गठबंधन के संकेत दिए

कोलकाता। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कवायद के बीच एक नया मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को साथ आने को कह रहे हैं, तो दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। केसीआर के साथ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मंच साझा कर चुके हैं। अब अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी गैर-कांग्रेस गठबंधन के संकेत दिए गए हैं। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपध्याय ने कहा कि सीएम ममता भाजपा के मुकाबले के लिए तैयार हैं। वे ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों के पास जाएंगी और भाजपा से मुकाबले के लिए बात करेंगी। हमारी पार्टी अपने रास्ते पर चलेंगी। हम भाजपा और कांग्रेस से दूरी बनाकर चलेंगे।

भाजपा का आरोप, केजरीवाल के घर पर रची गई थी शराब घोटाले की साजिश

नई दिल्ली। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की शराब नीतियों में परिवर्तन कर भ्रष्टाचार से काली कमाई करने की साजिश अरविंद केजरीवाल के घर पर रची गई। जिस बैठक में शराब नीतियों में परिवर्तन का निर्णय लिया गया, उसमें केजरीवाल के साथ-साथ सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और आप पार्टी के कई शीर्ष नेता उपस्थित थे। भाजपा का आरोप है कि इससे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी मॉडल का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि देश की न्यायिक प्रणाली अपने अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है, और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उन पर कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि देश में जिन राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, उनमें से लगभग सभी पर 2014 के पहले ही भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं।

मायावती ने कहा, नए मीडिया सेल का गठन होने तक कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मायावाती ने साफ तौर पर कहा कि नए मीडिया सेल का गठन होने तक कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा कि बीएसपी द्वारा पार्टी के मीडिया सेल का पुनर्गठन प्रस्तावित है। इस परिस्थिति में नए मीडिया सेल का गठन होने तक अब कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अत: श्री धर्मवीर चौधरी सहित पार्टी के जो भी लोग मीडिया में अगर अपनी बात रखते हैं तो वह उनकी निजी राय होगी, पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं। आपको बता दें कि मायावती के इस ट्वीट को धर्मवीर चौधरी ने भी रिट्वीट किया है। दरअसल, मायावती का यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी प्रवक्ता के रुप में धर्मवीर चौधरी माफिया अतीक अहमद के परिवार का बचाव कर रहे हैं। इससे पहले मायावती ने बुधवार को पार्टी संस्थापक कांशीराम के जन्मदिन पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और चुनावी सफलता और सत्ता की मास्टर चाबी हासिल कर विरोधियों को करारा जवाब देने का आह्वान किया था।

आईएस साजिश मामला: 2 बीटेक छात्रों ने क्रिप्टो में किया भुगतान, NIA ने दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देकर इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रची गई साजिश के संबंध में शिवमोग्गा इस्लामिक स्टेट (आईएस) साजिश मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एनआईए ने सितंबर 2022 में मामला फिर से दर्ज किया और आरोपी जबीउल्ला और अन्य द्वारा 15 अगस्त, 2022 को शिवमोग्गा (कर्नाटक) में प्रेम सिंह को छुरा घोंपने के बाद कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। शिवमोग्गा के माज मुनीर अहमद (23) और सैयद यासीन (22) पर आईपीसी की धारा 120बी, 121ए और 122, 1860, यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 18, 18बी, 20 और 38 और धारा 4 (i) और ES अधिनियम, 1908 की धारा 5 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम की धारा 2 के तहत आरोप लगाए गए हैं। माज़ और सैयद दोनों ही बी.टेक स्नातक हैं और एक ऑनलाइन विदेश आधारित हैंडलर द्वारा गोदामों, शराब की दुकानों, हार्डवेयर की दुकानों, वाहनों और एक विशेष समुदाय से संबंधित नागरिकों की संपत्तियों सहित सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को लक्षित करने के लिए कट्टरपंथी और प्रेरित थे।

संसदीय रिपोर्ट

रक्षा मामलों की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया खतरे में हैं 41 आयुध कारखाने

देश हित में नहीं बाहर से मिलिट्री सप्लाई पर निर्भरता

जितेंद्र भारद्वाज

रक्षा क्षेत्र से जुड़े तीन बड़े कर्मचारी संगठनों, जिनमें एआईडीईएफ, बीपीएमएस और सीडीआरए शामिल है, उन्होंने 220 साल पुराने 41 आयुध कारखानों के गौरवपूर्ण इतिहास के सिमटने की आशंका जाहिर की है। एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार के मुताबिक, 41 आयुध कारखानों को सात कंपनियों में तब्दील करने के बाद इनका अस्तित्व खतरे में है। इन कारखानों के निगमीकरण को अब डेढ़ साल हो गया है। केंद्र सरकार ने आयुध कारखानों के निगमीकरण के पक्ष में जवाबदेही, स्वायत्तता और दक्षता को लेकर यह तर्क दिया था कि इनका कारोबार बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। अभी तक यह वास्तविकता से दूर है।

रक्षा मामलों की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि सात डीपीएसयू ने 2024-25 रुपये में 26,300 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया है। 2021-22 का टर्नओवर लगभग 8686 करोड़ रुपये रहा है। श्रीकुमार ने 4 मार्च को सीडीएस द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था %हमारे लिए सबसे बड़ा सबक आत्मनिर्भर बनना है%। हम बाहर से मिलिट्री सप्लाई पर निर्भर नहीं रह सकते। तीनों कर्मचारी संगठन, निगमीकरण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

बतौर श्रीकुमार, केवल सीडीएस ही नहीं, बल्कि सेना प्रमुख भी इस बाबत इशारा कर चुके हैं। आर्मी चीफ ने गत दिनों कहा था कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, आयुध कारखानों को सरकार के तहत ओएफबी के रूप में अपनी मूल स्थिति में वापस लाना चाहिए। एक सरकारी संगठन के रूप में आयुध कारखानों को जारी रखने के लिए संघों और सीडीआरए द्वारा दिए गए

वैकल्पिक और व्यवहार्य प्रस्तावों पर विचार हो। संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि केंद्र सरकार की नीति 41 आयुध कारखानों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रही है। यह न तो सशस्त्र बलों और न ही देश के हित में है। मोदी सरकार ने एक अक्तूबर 2021 को 41 आयुध कारखानों को, उनकी ट्रेड यूनियनों के तमाम विरोधों को अनदेखा करते हुए उन्हें सात निगमों में परिवर्तित कर दिया था। इसके खिलाफ कर्मचारी संघ, अदालत में गए। वहां पर केंद्र ने अदालत में कहा, ईडीएसए-2021 को अगस्त, 2021 से आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इस पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण कर दिया।

इन सात कंपनियों में तब्दील हो चुके हैं ये कारखाने

वर्तमान में एआईडीईएफ, बीपीएमएस और सीडीआरए, तीनों कर्मचारी संगठनों ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष एक एजेंडा प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का आयुध कारखानों को कॉर्पोरेट बनाने का निर्णय एक विफलता और दुस्साहस है। इस पर पुनर्विचार करने और निर्णय वापसी की आवश्यकता है। 41 आयुध कारखानों को रक्षा पीएसयू अर्थात् म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया।

आयुध कारखानों के रक्षा नागरिक कर्मचारियों को 01.10.2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा गया। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि निगमीकरण एक विफल प्रयोग है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तैयारियों, 41 आयुध कारखानों और पूर्व ओएफबी कार्यालयों में कार्यरत रक्षा नागरिक कर्मचारियों के हित में वापस लिया जाना चाहिए। सरकार जिस निगम का दावा कर रही है, उसके लाभ के मामले में पारदर्शिता नहीं है। सरकार अपने उद्यम की सफलता का दावा करने की जल्दबाजी दिखाती रही है। संदिग्ध आंकड़ों के आधार पर सभी निगमों को छह माह के प्रदर्शन के आधार पर लाभदायक घोषित कर दिया गया।

टेंडर में प्रतिबंधात्मक शर्तें

आयुध कारखानों के निगमीकरण के बाद सशस्त्र बलों को अपनी जरुरतें पूरी करने के लिए बाजार की तरफ जाना पड़ रहा है। सेना से जुड़े जिन आइटमों को आयुध कारखानों में दशकों से गुणवत्ता के साथ और समय पर पूरा किया जाता रहा है, आज उन्हें सप्लाई ऑर्डर न देने की साजिश हो रही है। सी. श्रीकुमार बताते हैं, हाल ही एक टेंडर में ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तें रख दी गईं कि उसमें टीसीएल भाग ही न ले सके। इसके चलते 12 लाख नए डिजाइन की डिजिटल सेना वर्दी खरीद का मामला अटक गया। इसी तरह जीआईएल के तहत ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री की उपेक्षा की गई। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया (एफटीपी) के माध्यम से आपातकालीन खरीद के तहत 350 कॉम्बैट फ्री फॉल पैराशूट सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया। भारतीय वायु सेना ने भी 3,48,400 (ग्राउंड क्रू) (क्यू-3) की खरीद का सप्लाई ऑर्डर टीसीएल को देने की बजाए, उसका टेंडर जारी कर दिया।

दल से बिछड़ कर गांव पहुंचा हाथी का शावक

वन विभाग दल से मिलाने की तैयारी में जुटा, धमतरी जिले में बीच सड़क पर आ धमका

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में नन्हा हाथी अपने दल से भटक कर गांव में आ गया है. दल से बिछड़े हाथी शावक ने वन कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है. वन विभाग हाथी शावक की सतत निगरानी करने में लगा है और उसे दल से मिलाने की तैयारी में जुटा हुआ है. वहीं ग्रामीणों में हाथी के शावक को देखने की होड़ मची हुई है. हाथी शावक ने गांव में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है।

वन मंडल अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस हाथी शावक की रात और दिन को सतत निगरानी करने के लिए वन कर्मियों के दो अलग-अलग दल तैनात कर दिए गए हैं।

ऐसी संभावना है कि राज्य की सीमा से लगा जंगल के किनारे पत्तों में आग के चलते अपने हाथियों के दल से यह शावक भटक गया है. इसी वजह से शावक तपकरा क्षेत्र के मृगखोल गांव के आसपास में विचरण कर रहा है. जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके में आ जाने से इस नन्हे शावक से ग्रामीणों को भले खतरा नहीं है. लेकिन हाथी शावक की आवारा कुत्ते तथा अन्य खतरों से लगातार देखरेख करनी पड़ रही है.

वन विभाग ने इस हाथी के शावक को उसके दल से मिलाने के प्रयास में जुट गई है. इसके लिए वन अधिकारियों ने पड़ोसी राज्य ओड़िसा और झारखंड के वन अधिकारियों से सम्पर्क करना शुरू कर दिया है।

चार माह पहले भी बिछड़ा था शावक

इस घटना के 4 माह पहले भी एक अन्य हाथी शावक अपने दल से बिछड़ कर तपकरा का समडमा गांव आ गया था. वन विभाग को उसे विश्राम गृह में पशुचिकित्सक की देखरेख में रखना पड़ा था. उस नन्हे शावक को भी हाथियों के दल से मिलवाने के सभी प्रयास विफल हो जाने के बाद, अंततः तमोर पिंगला हाथी सरंक्षण गृह में भेजा गया था।

अचानक बीच सड़क पर आ धमका भयानक हाथी जान बचाने बाइक छोड़कर भागा

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथियों के उत्पात मचाने की घटना देखने को मिलती रहती है। कभी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी सड़कों पर लोगों के लिए मुसीबत बनकर घूमते हुए नजर आ जाते हैं।

इसी बीच चारगांव जबर्रा इलाके में जंगलों के बीच वन विभाग के कर्मचारी जब दफ्तर से ड्यूटी कर घर जा रहे थे तभी हाथी बीच सड़क पर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इसके बाद डर के मारे वन कर्मचारी अपनी बाइक को दूर छोड़कर भागने लगा। वन कर्मचारी को भागता देख हाथी ने उसे दौड़ाया। हाथी ने वन कर्मचारी के बाइक को पटक दिया। यह पूरा चारगांव जबर्रा इलाका है जिले में लगातार हाथियों का आतंक को देखते हुए वन विभाग की टीम ने आस- पास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है।

कटघोरा में अंबिकापुर नेशनल हाईवे को पार करते दिखा दंतैल हाथी, इलाके में दहशत

कोरबा। कोरबा के कटघोरा में अंबिकापुर नेशनल हाईवे को पार करते हुए एक दंतैल हाथी दिखाई दिया है। इस दौरान सड़क की दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। हाथी की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल है। केंदई रेंज के परला-चोटिया के पास हाथी दिखाई दिया है। कटघोरा वन मंडल इलाके में 40 से ज्यादा हाथियों का दल कर विचरण कर रहा है।

जनजाति वर्ग के लोगों से संबंधित प्रकरणों का त्वरित व समय सीमा में करें निराकरण: पोटाई

- **छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने अजजा वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में दिए निर्देश**

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने पंचवटी विश्राम गृह के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए संचालित शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। पोटाई ने बैठक में रखे गए एजेंडों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि विभागों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की तरफ से आए मांगों व शिकायतों का निराकरण समय सीमा पर कर उनको लाभ और न्याय दिलाया जाए।

उन्होंने कहा कि एनएच निर्माण में आदिवासी वर्ग के लोगों से ली गई जमीन के मुआवजा विसंगति संबंधी शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। बैठक में भू-अंतरण मामलों को लेकर भी चर्चा की गई और प्रकरणों का निराकरण करने के साथ ही इसकी जानकारी आयोग को देने के निर्देश दिए। पोटाई ने कहा कि आदिवासी वर्ग के लोगों की जमीन पर अन्य वर्ग के लोग द्वारा जबरन काबिज होने की प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया जाए।

समीक्षा बैठक में इसके लिए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। पोटाई ने कहा कि मिसल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की वजह से भोरिया जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कत और आरक्षण के लाभ से वंचित होने की शिकायत सामने आई है। उन्होंने इस तरह की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक उदय किरण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सेवा राम दीवान सहित स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग व अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में पोटाई ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा, राशन कार्ड और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, आदिवासी छात्रावासों की स्थिति और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी की विस्तृत जानकारी ली। इसके अलावा जनजाति वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, विभागों में कार्यरत अजजा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या व स्थिति, एसईसीएल की खदानों में आदिवासी वर्ग के लोगों से ली गई जमीन के बदले नौकरी मुआवजा व पुनर्वास सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में पोटाई ने अजजा वर्ग से संबंधित पुलिस कार्यवाही, चिटफंड से संबंधित प्रकरणों का भी समय पर निराकरण के निर्देश दिए।

दूसरे के खेत को अपना बताकर रायपुर के शातिर ने किसान को लगाया चूना, केस दर्ज

दुर्ग। रायपुर के शातिर बदमाश ने दुर्ग जिले के जामगांव में दूसरे के खेत को अपना बताकर धमतरी के किसान को 30 लाख रुपए का चूना लगा दिया। खेत का सौदा होने के बाद टोकन मनि व रजिस्ट्री के नाम पर 30 लाख 100 रुपए ले लिए और रजिस्ट्री भी नहीं की। बार बार रजिस्ट्री के लिए आनाकानी करने पर परेशान किसान ने जामगांव आर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धारा 120-बी, 294, 420, 467, 468, 471, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।

दरअसल सेमरा गांव जिला धमतरी निवासी जगदीश साहू को किसान खेती के लिए पाटन क्षेत्र में जमीन की तलाश थी। इस दौरान उसकी मुलाकात श्यामू यादव निवासी ग्राम ढौर थाना पाटन से हुई। श्यामू यादव ने उसे अमरपुरी चौंक सुन्दर नगर रायपुर निवासी अश्वनी कुमार डडसेना से मिलवाया। अश्वनी डडसेना ने बताया कि उसके पास 8 एकड 52 डिसमिल जमीन ग्राम रीवागहन, जामगांव आर तह पाटन में स्थित है। अश्वनी ने उसका खसरा नंबर 400,401,407/1 कुल रकबा 8 एकड 52.5 डिसमिल बताया। इसके बाद जगदीश साहू ने उक्त जमीन को खरीदने अपनी सहमति दे दी।

इसके बाद जमीन का सौदा प्रति एकड़ 12 लाख 75000 रुपए में हुआ। सौदा तय होने के बाद जगदीश साहू ने टोकन के रूप में 2 लाख 100 रुपए दो गवाहो के समक्ष दिया। इसके बाद अश्वनी कुमार डडसेना ने 7 नवंबर 2022 को एक इकरारनामा भी बनाया। इसके बाद अश्वनी डडसेना ने रुपयो की आवश्यकता बताई तो अपने परिचित राहुल कुमार के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के खाता क्रमांक 101009175793 शाखा सेलूद जिला दुर्ग से चेक क्रमांक 006594 के माध्यम से 22 लाख 44 हजार 403 रुपए व पत्नी नंदिनी साहू के एसबीआई शाखा भखारा के खाता क्रमांक 37803004205 से चेक क्रमांक 047813 के माध्यम से 5 लाख 55 हजार 597 रुपए 10 नवंबर 2022 को दिया। इस प्रकार अश्वनी कुमार डडसेना को 30,00,100 भुगतान कर दिया।

जगदीश साहू ने अपनी शिकायत में बताया कि रकम लेने के बाद अश्वनी डडसेना रजिस्ट्री के लिए घुमाने लगा। कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए कहने पर टालने लगा। इस बीच अश्वनी डडसेना ने रजिस्ट्री में जरूरत के नाम नी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा भखारा तीन चेक ले लिए। चेक लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके बाद तंग आकर जगदीश साहू ने अपने पैसे व चेक वापस मांगे तो आज कल कहते हुए न तो रकम लौटाई और न ही चेक दिए। उल्टे जान से मारने की धमकी, गाली गलौच करने के साथ ही जगदीश साहू व उसके बेटे को बलात्कार के केश में फंसाने की धमकी दी। डरे सहमे जगदीश साहू ने आखिरकर इस मामले में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

निगम क्षेत्र में गांवों को शामिल करने मेयर इन काउंसिल की स्वीकृति

दुर्ग। नगर पालिक निगम के डाटा सेंटर हॉल में मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर धीरज बाकलीवाल के अध्यक्षता और आयुक्त लोकेश चन्द्राकर की मौजूदगी में विकास कार्यों सहित अन्य विषयों को लेकर आयोजित की गई। बैठक में अहम मुद्दो पर चर्चा की गई,बता दे कि वर्ष 2023-24 के आय व्यय अनुमान पत्रक पर विस्तार से चर्चा की गई।इसके अतिरिक्त फिल्टर प्लांट 24,42 एवं 11में पेयजल शुद्धि करण हेतु एलम खरीदी को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मिनीमाता चौक से अंडा मार्ग में आ रहे पाइप लाइन को शिफ्टिंग पर 76.83 लाख के प्रस्ताव को परिषद में प्रस्तुत किया गया। कसारीडीह तालाब सौंदर्यकरण एवं गोकुलनगर गौठान में आवश्यक सुविधा कार्य एवं निर्माण हेतु निविदा की न्यूनतम दर को स्वीकृति प्रदान की गई। शहर में गन्ना रस विक्रेताओं से पूर्व वर्ष के अनुसार 4840/ तीन माह के लिए दर की स्वीकृति दी गई। निगम क्षेत्र में विकास की संभावना को देखते हुए 10 गांव हनोदा, धनोरा, महमरा, चिखली, जेवरा सिरसा, अंजोरा, पिसेगांव, कोलिहापुरी, मोहलाई, कोटनी के अतिरिक्त कोडिया, चंदखुरी एवम खपरी गांव को दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसके अतिरिक्त 15 वे वित्त के अलावा राजेन्द्र पार्क के संचालन व्यवस्था को स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित करने राजस्व आय को बढ़ाने पर गहन चर्चा परिषद में की गई। इसके साथ ही सफाई व्यवस्थाओं के अलावा राजस्व की स्थित के साथ साथ एमआईसी सदस्यों के साथ विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई। बैठक में मआईसी सदस्य अब्दुल गनी, संजय कोहले, दीपक साहू, ऋषभ जैन, जयश्री जोशी, हमीद खोखर, सत्यवती वर्मा, भोला महोविया, शंकर ठाकुर, मनदीप सिंह भाटिया,अनूप चंदनिया, सुश्री जमुना साहू उपायुक्त मोहेंद्र साहू, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर,एसडी शर्मा, आरके पांडेय, जितेंद्र समैया, आरके पालिया, प्रकाशचंद थवानी,संजय ठाकुर, राजकमल बोरकर,जावेद अली,शरद रत्नाकर,थानसिंह यादव आदि मौजूद रहें।

पटवारी के पास से 5.26 लाख रुपए जब्ती, एसडीएम ने किया निलंबित

दुर्ग। कोहका पटवारी कार्यालय से दुर्ग एसडीएम ने पांच लाख 26 हजार 305 रुपये की जब्ती बनाई है। एसडीएम कार्यालय में छापा मारने पहुंचे तब पटवारी शत्रुघ्न मिश्रा एक बैग में उक्त रकम को रखा हुआ था। एसडीएम के पूछने पर पटवारी ने उक्त रकम को कभी आपरेटर तो कभी तहसीलदार का होना बताया। कड़ाई से पूछताछ पर पटवारी रकम कहां से मिली इसका जवाब नहीं दिया। मामले में रकम जब्त कर पुलिस के सुपुर्दगी में दे दी गई है और पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।

एसडीएम लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि कोहका के पटवारी हल्का नंबर 45 में पदस्थ पटवारी शत्रुघ्न मिश्रा के खिलाफ लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत पर एसडीएम लक्ष्मण तिवारी गुरुवार शाम जांच के लिए पटवारी कार्यालय में छापा मारा। इस दौरान पटवारी अपने कक्ष में मौजूद था। जांच के दौरान एसडीएम की नजर एक काले रंग की बैग पर पड़ी।

जिसे खुलवाने पर उसमें पांच लाख 26 हजार रुपये नगद रकम होना पाया गया। एसडीएम ने रकम कहां से आई इस संबंध में पटवारी से पूछताछ शुरू की। पटवारी उक्त रकम कभी आपरेटर का तो कभी तहसीलदार का होना बता रहा था। एसडीएम की फटकार लगाई तो पटवारी रकम के स्त्रोत के संबंध में जवाब नहीं दिया। इस पर एसडीएम ने पुलिस को बुलाया और बैग सहित रकम की जब्ती बनाई। एसडीएम ने बताया कि पटवारी को निलंबित कर विभागीय जांच की जा रही है। पटवारी शत्रुघ्न मिश्रा यहां तीन साल से पदस्थ है। एसडीएम ने बताया कि कुछ महीने पहले उसका तबादला हुआ था लेकिन उसने हाईकोर्ट से स्टे ले आया है। शत्रुघ्न मिश्रा के खिलाफ किस तरह की शिकायत मिली है इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि विभागीय जांच के दौरान सारी शिकायतें सामने आ जाएंगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पंचायत सचिव गए हड़ताल पर, सात के प्रभार बदले

कोरबा। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर गुरुवार से पंचायत सचिव काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सचिवों का कहना है कि शासकीयकरण की मांग को बजट में शामिल नहीं किया गया है। इससे नाराजगी है। इधर जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने सात सचिवों के प्रभार में फेरबदल कर दिए है। पंचायत सचिव ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में आईटीआई चौक के पास धरना शुरू हुआ। सचिव संघ के अध्यक्ष संतलाल का कहना है कि नियमितीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके बाद भी 1 सूत्रीय मांग भी पूरी नहीं की गई है। इधर जिला पंचायत सीईओ ने कोरबा और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के सात पंचायत सचिवों के प्रभार में फेरबदल किया है। अजगर बहार के सचिव दुबराज सिंह को चुईया पंचायत का भी प्रभाव दिया है। यहां की सचिव नविता दुबे को पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के पाथा पंचायत भेजा है। भैंसमा सचिव राजेश बैरागी को कुदमुरा और पाथा सचिव पितांबर सिंह को भैंसमा भेजा गया है।

फर्जी साइन कर सगे भाई ने निकाल ली बीमा की रकम

भिलाई। सुपेला थाना अंतर्गत एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से फर्जी हस्ताक्षर कर एक शख्स ने बीमा की रकम ऐंट ली है। सख्स ने अपनी सगी बहन को ही चूना लगा दिया। इस मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके भाई के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुपेला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 सी क्रास स्ट्रीट 01, सेक्टर 1 भिलाई निवासी मार्शलीना सेंटियागो ने अपने भाई आगस्टीन सेंटियागो के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पिता उनके पिता बीएसपी के अग्निशमन विभाग से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त पश्चात एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मे 2,30,000 रुपए का बीमा लिया। कोराना महामारी के दौरान माता पिता की मृत्यू हो गई। उसके बाद प्रार्थी के भाई आगस्टीन सेंटियागो ने अपनी एक महिला मित्र शीतल स्वामी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और कर फर्जी तरीके से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से रुपए निकाल लिए।

पिस्टलनुमा हथियार से गार्डों को धमकाया, 2 गिरफ्तार

कोरबा। दर्री थाना क्षेत्र के एनटीपीसी कॉलोनी ऊर्जा द्वार पर तैनात निजी सुरक्षा गार्डों को दो युवकों ने पिस्टलनुमा हथियार के बल पर धमकाया। बुधवार की रात करीब 8.30 बजे हुई घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार बाइक क्रमांक सीजी 12 एवाई 5582 में सवार दो युवक एनटीपीसी कॉलोनी जमनीपाली के ऊर्जा द्वार से रांग साइड से आगे निकलने का प्रयास किया। इस पर ड्यूटी पर तैनात एनटीपीसी के निजी गार्डों ने बाइक को रोका। वाहन में सवार दोनों युवक बहसबाजी करते हुए अपशब्द कहकर अपने पास रखे पिस्टलनुमा हथियार दिखाकर डराया धमकाया। इसकी सूचना दर्री थाना के प्रभारी निरीक्षक विवेक शर्मा को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चित्रकांत पंत 28 पिता यशवंत दास व रेशम दास 26 पिता सुखदेव दास दोनों निवासी ग्राम रोहिना थाना बांकीमोंगरा को पकड़ा। इनके कब्जे से पुलिस ने पिस्टलनुमा हथियार भी जब्त किया है।

बिजली विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी

कोरबा। कोरबा में बिजली कंपनी में अनुकंपा पर नियुक्ति करने वाले एक कर्मचारी ने युवक को तीन लाख रुपये की चपत लगाई है। इसी कंपनी में रोजगार दिलवाने का झांसा देकर युवक से धोखाधड़ी की गई। पीड़ित पक्ष ने मामले की रिपोर्ट मानिकपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई है। मुड़ापार में रहने वाले प्रमोद गुप्ता ने ठगी के मामले की लिखित शिकायत मानिकपुर पुलिस से की है। प्रमोद ने बताया कि कुछ समय पहले ढोडीपारा के गजेंद्र राठौर से उसकी जान पहचान हुई थी। परिचय होने के बाद उसने बिजली कंपनी में अपने प्रभाव की जानकारी दी खुद को अधिकारियों से पहुच और रिश्तेदार बताया फिर युवक को झांसे में ले लिया इसके बाद में नौकरी लगवाने की बात कही गई। जिसके बदले तीन लाख रुपये ले लिए। जब पीड़ित युवक ने ज्वाइनिंग लेटर देने की बात की तो वह टाल-मटौल करने लगा। नौकरी नहीं लगने पर राठौर से रुपयों की डिमांड की गई तो उसने चेक दिया जो बाउंस हो गया। ठगी के इस मामले के बारे में पूरी जानकारी मानिकपुर पुलिस चौकी को दी गई है।

महादेव बुक पैनल का आरोपी लक्की चकमा दे हुआ फरार

भिलाई नगर। ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक का पैनल संचालित करने वाले आरोपी लक्की को गिरफ्तार करने के लिए भट्टी पुलिस पहुंची हुई थी कि परिजनों ने ऐसा विरोध किया कि वह फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं वैशाली नगर पुलिस ने झारखंड, बिहार व रामनगर सुपेला के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महादेव आईडी एम-229 के मास्टर माइंड फ्रैंस कैफे के अभय कुमार फरार हो गया। पुलिस ने यहां से एक लैपटाप, दस मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते बरामद किए। कल रात्रि भट्टी पुलिस के द्वारा सेक्टर 2 में गाडियों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक चार चक्का गाड़ी को रोका गया जिसमें राजबीर सिंह निवासी आनंद चौक पांच रास्ता सुपेला भिलाई का मोबाइल चेक करने पर महादेव आईडी के लिए एकाउंट नंबर और आईडी, लकी निवासी सेक्टर-4 के द्वारा उपलब्ध कराया जाना जांच में मिला। इसी सूचना पर भट्टी पुलिस द्वारा लक्की के घर आज अलसुबह सेक्टर 4 में दबिश दी गई।

सफाई कार्यों में लापरवाही हुई तो ठेकेदार व निरीक्षक होंगे जिम्मेदार

कोरबा। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने साफ-सफाई कार्यो में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा है कि सफाई कार्यो में यदि उदासीनता बरती गई, निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई के कार्य नहीं हुए तथा लापरवाही सामने आई तो स्वच्छता कार्यो के संबंधित ठेकेदार व निरीक्षक, पर्यवेक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे एवं उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि पर्याप्त कर्मचारी, मशीनरी व संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बाद भी यदि सफाई कार्यो में उदासीनता बरती गई, तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर शहर के साफ-सफाई कार्यो, नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुड़े कार्यो, शासकीय योजनाओं, निर्माण व विकास कार्यो सहित निगम के अन्य विभिन्न कार्यो की कार्यप्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होने साफ-सफाई कार्यो की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि नियमित रूप से निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई कार्य किए जाएं, नालियों की सम्पूर्ण सफाई पर विशेष फोकस किया जाए ताकि नालियों में जाम की स्थिति न बने, प्रत्येक वार्ड के लिए पृथक-पृथक स्वच्छता सुपरवाईजर नियुक्त किए गए हैं, वे सुनिश्चित कराएं कि निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई हों, उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि सफाई कार्यो में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित पर कड़ी कार्यवाही होगी। आयुक्त पाण्डेय ने निगम के निर्माण व विकास कार्यो की जोनवार व मदवार कार्यप्रगति की समीक्षा की। उन्होने अधोसंरचना मद, वित्त आयोग मद, जिला खनिज न्यास मद, प्रभारी मंत्री मद, सांसद व विधायक मद, महापौर मद, पार्षद व एल्डरमेन मद, मरम्मत संधारण, निगम मद सहित अन्य मदो के अंतर्गत प्रस्तावित व प्रगतिरत कार्यो की जोनवार समीक्षा करते हुए कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होने कहा कि जिन निर्माण एजेंसियों द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी कार्य प्रारंभ करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही, उन्हें ब्लेक लिस्टेड किए जाने की कार्यवाही करें। शासकीय योजनाओं की समीक्षा - बैठक के दौरान आयुक्त पाण्डेय ने शासकीय योजनाओं की कार्यप्रगति की योजनावार समीक्षा की, उन्होने गोधन न्याय योजना अंतर्गत निगम के समस्त गोठानों व गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर की खरीदी, खाद के निर्माण की समीक्षा करते हुए खाद निर्माण व विक्रय में तेजी लाने के निर्देश दिए, उन्होने अधिकारियों से कहा कि सक्रिय गोबर विक्रेताओं की संख्या बढ़ाएं।

शासन प्रशासन के प्रयासों से प्रशासनिक सुविधाएं हो रही सुदृढ़

दंतेवाड़ा। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास हेतु विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इन्हीं कार्यों में से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए विकासखंड कुआकोंडा अंतर्गत ग्राम पंचायत खुटेपाल अंतर्गत नवीन ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत खुटेपाल वर्ष 2020 से पहले ग्राम पंचायत श्यामगिरी का आश्रित ग्राम था। जिसे बाद में एक नवीन पंचायत बनाया गया।

नवनिर्मित ग्राम पंचायत खुटेपाल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू तौर पर लागू करने एवं ग्रामीणों को शासकीय योजना का लाभ सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रशासनिक भवन की आवश्यकता थी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नवनिर्मित ग्राम पंचायत खुटेपाल की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से प्रदान की गई। अधिकारी एवं तकनीकी सहायक सहित कर्मचारियों की तत्परता एवं प्रयासों से जल्द ही नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। मनरेगा अंतर्गत इस कार्य में 1.16 लाख मजदूरी राशि, 601 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ। इससे 36 श्रमिक परिवार लाभांवित हुए। नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो जाने से अब ग्राम पंचायत खुटेपाल के निवासियों को अपना प्रशासनिक भवन मिल चुका है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

रक्षा क्षेत्र में प्रस्तावों को मंजूरी 'आत्मनिर्भरता को बढ़ावा'

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में 70,500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी देने को शुक्रवार को ''आत्मनिर्भरता को बढ़ावा'' देने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताते हुए कहा कि यह भारतीय प्रतिभा में विश्वास की पुन: पुष्टि करता है। गौरतलब है कि भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी थी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। डीएसी ने सैन्य साजो-सामान की खरीद के लिए 70,584 करोड़ रुपये की 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' को स्वीकृति दी थी, जिसके तहत सभी खरीद 'स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित' श्रेणी के तहत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लोगों से मतुआ महा मेला में शिरकत करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी के श्रीधाम ठाकुरनगर में 19 से 25 मार्च तक मतुआ महा मेला का आयोजन किया जाएगा।

भारत की चुनौतियों पर विदेश में बात करना अशोभनीय : वरुण

नई दिल्ली। भाजपा सांसद और अक्सर अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों पर खुल कर विरोध जताने वाले वरुण गांधी का एक और ट्वीट चर्चा में है। हालांकि इस बार उन्होंने जो बात कही है उसे उनके ही चचेरे भाई राहुल गांधी पर तंज के रूप में भी देखा जा सकता है। वरुण गांधी ने दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनियन के उस आमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिसमें उनसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं विषय पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में वरुण गांधी ने कहा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर घरेलू चुनौतियों को उठाने की कोई योग्यता या समग्रता नजर नहीं आती और इस तरह का कदम एक अपमानजनक कार्य होगा। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक बहस के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। भारत की पसंद और चुनौतियों को अंतरराष्ट्रीय जांच के अधीन करना मेरे लिए एक अशोभनीय कार्य है।

कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ लाई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने उनके इस बयान के आधार पर ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है और आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया में ही पीएम की यह बातें न सिर्फ अपमानजक थी, बल्कि नेहरु परिवार के सदस्यों खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि लोकसभा सदस्य भी हैं, उनके प्रति असम्मानजनक और मानहानि वाली थीं।

भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार को घेरा

नईदिल्ली। दिल्ली की राजनीति में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी जारी है। एक बार फिर से भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली की सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नियमों को ताख पर रखा। अब भ्रष्टाचार का लेखाजोखा सामने आ रहा है। भाजपा ने दावा किया कि आबकारी नीति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में बदली गई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार आप के बड़े नेताओं के संज्ञान में था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नई-नवेली पार्टी से लेकर पुरानी पार्टी तक... ये सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने-अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि विगत कई महीनों से कभी इस मुद्दे का सहारा लेकर तो कभी उस मुद्दे का सहारा लेकर वह ऐसा शोर-शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या तो झुठलाया जा सके।

पांच दिन और बढ़ी मनीष सिसोदिया की हिरासत

नईदिल्ली। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सिसोदिया की हिरासत शुक्रवार को खत्म हो गई थी। ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हिरासत सात दिन और बढ़ाने की मांग कोर्ट से की। कोर्ट ने ईडी की मांग पर मनीष सिसोदिया की हिरासत को 5 दिन और बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। सिसोदिया को दो दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पिछले महीने गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि उसने सिसोदिया के क्लाउड डेटा को पुन: प्राप्त कर लिया था, जिसमें 1.23 लाख ईमेल डंप थे, और डेटा की फोरेंसिक जांच के लिए समय की आवश्यकता थी।

राहुल गांधी और अदाणी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा

संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा अडाणी समूह के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी गठित करने की मांग पर विपक्ष के हंगामे तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल में लंदन में दिये गये बयान पर उनसे माफी मंगवाने की मांग पर सत्ता पक्ष के अड़े रहने के कारण शुक्रवार को भी दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा। लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण पूरे सप्ताह एक भी दिन प्रश्नकाल एवं शून्यकाल समान्य ढंग से नहीं चल पाये और कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो पाया। लोकसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के शोर-शराबे के कारण कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया और प्रश्न पूछने के लिए कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी का नाम पुकारा।

इस बीच कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उधर सत्तापक्ष के कुछ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर विदेश में राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिये गये बयान पर उनसे माफी की मांग करने लगे। कांग्रेस नेता तिवारी ने पूरक प्रश्न पूछने के लिए सदन में व्यवस्था नहीं होने का उल्लेख किया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा जारी था। सत्ता पक्ष के सदस्य 'राहुल गांधी माफी मांगो' के नारे लगा रहे थे जबकि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य 'बोलने दो, बोलने दो..राहुल जी को बोलने दो' के नारे लगा रहे थे। इस दौरान सदन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य है कि वो सांसद हैं। सही मायने में ये दुर्भाग्य है कि वो सांसद हैं क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा हैं उसको ही बदनाम करने और उसके बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। उनको बिना शर्त के माफी मांगनी

चाहिए।

सदन के उप नेता राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से व्यवस्था बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि सदस्यगण सदन चलने दें। उन्होंने कहा, ''आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है।'' उन्होंने कहा कि सदन में व्यवस्था बनेगी तब वे सभी को बोलने का मौका देंगे। बिरला ने सदस्यों से कहा कि इस तरह से खड़े रहेंगे (आसन के पास) तो कार्यवाही नहीं चलेगी। हंगामा नहीं थमने पर अध्यक्ष बिरला ने सदन की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य कर्णेंदु भट्टाचार्य के निधन का उल्लेख किया। सदन में मौजूद सदस्यों ने भट्टाचार्य के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

सभापति ने इसी बीच, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के तहत सदन के नेता पीयूष गोयल को 13 और 14 मार्च को सदन में किए गए दावों को प्रमाणित करने का निर्देश दिया। धनखड़ ने कहा, ''विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में, मुझे लगता है कि सदन के नेता को इस मुद्दे पर 13 और 14 मार्च को उनके द्वारा किए गए दावों को प्रमाणित करने का निर्देश देना उचित है।'' धनखड़ ने कहा कि अडाणी समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने में सरकार की विफलता को लेकर 11 सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उनके मुताबिक नोटिस देने वालों में कांग्रेस के नीरज डांगी, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुमार केतकर, सैयद नासिर हुसैन, रंजीत रंजन, के सी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ सदस्य शामिल थे। धनखड़ ने कहा कि बहुत सोच-विचार करने के बाद उन्होंने किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया है।

सभापति के यह कहने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरु कर दी। इसी दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र को लेकर लंदन में की गई उनकी टिप्पणी का मुद्दा उठाया और यह कहते हुए हंगामा करने लगे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगें। धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक 11 बजकर करीब 17 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। ज्ञात हो कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष के सदस्य लंदन में राहुल गांधी द्वारा भारतीय लोकतंत्र के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विदेशी दौरों के दौरान पूर्व में भारत को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। विपक्षी सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग को लेकर लगातार हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं।

सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। यह नोटिस गोयल द्वारा लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के बयान का उच्च सदन में उल्लेख करने के लिए दिया गया है। इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने अडाणी समूह के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद भवन के परिसर में धरना दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस धरने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खरगे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना (उद्धव) की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी तथा कई अन्य सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने 'वी वांट जेपीसी' के नारे भी लगाए गए।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की खिंचाई की

राहुल राष्ट्र-विरोधी टूलकिट का हिस्सा हैं

नयी दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर देश और विदेश में संसद का अपमान करने का आरोप लगाया। नड्डा ने यह भी कहा कि राहुल लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना करते हुए राष्ट्र-विरोधी टूलकिट का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, कांग्रेस अब देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है...राहुल गांधी अब इस राष्ट्रविरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ काम करने वाले ''टूलकिट का स्थायी हिस्सा'' बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों से ''हस्तक्षेप'' की मांग करने के लिए माफी मांगनी होगी। नड्डा ने एक बयान में कहा कि भारत विरोधी ताकतों को हमेशा से दृढ़ भारत, उसके मजबूत लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर भारत में लोकतंत्र की स्थिति की आलोचना करके और अमेरिका तथा यूरोप के हस्तक्षेप की मांग करके गांधी ने देश की सम्प्रभुता पर हमला किया है।

नड्डा ने कहा, '' लोगों द्वारा बार-बार अस्वीकार किए जाने के बाद राहुल गांधी भारत के खिलाफ काम करने वाले ''टूलकिट'' का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। '' उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रमुख पर ब्रिटेन में भारत, उसकी संसद, उसकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है, जिसने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि गांधी ने विदेशी धरती पर जो किया, उससे देश के खिलाफ काम करने वालों को मजबूती मिली है। नड्डा ने कहा, ऐसे समय में जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और यहां जी20 बैठकें

हो रही हैं, राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और उन्होंने संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा की जा रही आलोचना का जवाब देने के लिए संसद में बोलने की अनुमति मांगी है।

नड्डा के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया तीखा प्रहार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा, मैं जेपी नड्डा के बयान की निंदा करता हूं। वो खुद राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरो को वो राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं। यही नहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वह लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने का मौका देंगे तो वह अपनी बात जरूर रखेंगे। मगर बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है इसलिए उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। खड़गे ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि वो क्यों नहीं राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका दे रही? मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा को राष्ट्रविरोधी करार देते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है वह अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कभी राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी हो सकते हैं?

खेल
प्रमुख समाचार

वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया से 16 साल बाद वनडे जीता भारत

तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई

मुंबई। भारत ने मुंबई के वानखेड़े में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 35.4 ओवर में 188 रन पर सिमट गई थी। कंगारुओं के लिए मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 81 रन की पारी खेली थी। जवाब में भारत ने 39.5 ओवर में पांच विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने लय में वापसी की और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 91 गेंदों में 75 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा रवींद्र जडेजा भी 45 रन बनाकर नाबाद रहे। लक्ष्य का पीछा करते हुए एक वक्त भारत ने 39 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद राहुल ने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 44 रन की साझेदारी निभाई। हार्दिक के आउट होने के बाद जडेजा और राहुल के बीच छठे विकेट के लिए 108 रन की नाबाद साझेदारी हुई। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अब अगला वनडे रविवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 16 साल बाद हराया है। दोनों के बीच इस मैदान पर पांच वनडे खेले गए हैं। इसमें से भारत ने तीन और ऑस्ट्रेलिया ने दो मुकाबले जीते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 355 अंक चढ़ा निफ्टी 17,100 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज यानी शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 355 अंक मजबूत हुआ, वहीं निफ्टी 114 अंकों की बढ़त के साथ 17,100 के पार निकल गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 355.06 अंक यानी 0.62 फीसदी मजबूत होकर 57,989.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऊंचे में 58,178.94 तक गया और नीचे में 57,503.90 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (हस्थ) का निफ्टी 114.45 अंक यानी 0.67 फीसदी चढ़ा। निफ्टी कारोबार के अंत में 17,100.05 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ऊंचे में 17,145.80 तक गया और नीचे में 16,958.15 तक आया।

बैंक में विनिवेश की प्रक्रिया सही दिशा में

नई दिल्ली। निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को बताया कि यह अटकलें भ्रामक हैं कि सरकार आईडीबीआई बैंक के चार अरब डॉलर के विनिवेश को टाल सकती है क्योंकि निजीकरण का सौदा सही राह पर है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रकिया निर्धारित रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया के मुताबिक चल रही है। डीआईपीएम ने मीडिया में आई उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि आईडीबीआई का विनिवेश टल सकता है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा कि बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री अभिरुचि पत्र (ईओआई) के चरण से आगे निकल गई है। दीपम सचिव तुहीन कांत पांडेय ने ट्वीट किया, ''विभिन्न ईओआई मिलने के बाद लेनदेन अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है।''

फोनपे को वॉलमार्ट से मिला 20 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त फंड

नईदिल्ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच फोनपे ने शुक्रवार को कहा कि उसने 12 अरब डॉलर के निवेश या वित्तपोषण से पहले के मूल्यांकन (प्री-मनी वैल्यूएशन) पर वॉलमार्ट से अतिरिक्त 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,649 करोड़ रुपये) की प्राथमिक पूंजी जुटाई है। पिछले वर्ष अपना मुख्यालय भारत स्थानांतरित करने के बाद से फोनपे एक अरब डॉलर तक की पूंजी जुटाने की कवायद कर रही है। यह नया वित्तपोषण भी उसी का हिस्सा है। फोनपे ने एक बयान में कहा कि इस वित्तपोषण के साथ कंपनी विभिन्न वैश्विक निवेशकों से 65 करोड़ डॉलर (लगभग 5,360 करोड़ रुपये) जुटा चुकी है। निवेश या वित्तपोषण से पहले का 12 अरब डॉलर का मूल्यांकन वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फोनपे को देश की सबसे मूल्यवान वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनी बनाता है।

क्रेडिट सुइस संकट से भारतीय बैंकिंग तंत्र पर नहीं पड़ेगा कोई असर: विशेषज्ञ

नईदिल्ली। क्रेडिट सुइस में आए संकट से भारतीय बैंकिंग तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में इसकी उपस्थिति बहुत कम है। विशेषज्ञों ने यह दावा किया है। जेफ्रीज इंडिया की रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि सिलिकॉन वैली बैंक की तुलना में क्रेडिट सुइस भारतीय वित्तीय तंत्र के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड के बैंक की परिसंपत्तियां 20,000 करोड़ रुपये से कम (विदेशी बैंकों में 12वां) हैं। ये बैंक डेरिवेटिव बाजार में मौजूद है और इनकी संपत्ति का 60 फीसदी कर्ज से है, जिसमें से 96 फीसदी दो महीने तक के लिए ही है। इसकी संपत्तियों में हिस्सेदारी 0.1 फीसदी ही है, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिहाज से काफी कम है। क्रेडिट सुइस का मुख्यालय ज्यूरिख में है और भारत में इसकी सिर्फ एक शाखा है।

देश की अर्थव्यवस्था में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी

संजय तिवारी

पूंजी और केन्द्रीकरण ये एक दूसरे के साथी हैं। केन्द्रीकरण पूंजी का स्वभाव है इसलिए अगर हम भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि भारत में उत्पादन और पूंजी का विकेन्द्रीकरण इसकी समृद्धि का आधार रहा है। जब भारत संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था उस समय भारत का उत्पादन तंत्र यहां की जातियों में निहित था। यानी यह पूरी तरह से विकेन्द्रित था।

भारतीय अर्थव्यवस्था में गांव इसकी मूल ईकाई हुआ करते थे और उत्पादन केन्द्र भी। गांव के लोगों की जरूरत की जितनी चीजें थीं उन्हें अधिकांशत: गांव में ही बनाया जाता था। जो अतिरिक्त वस्तुएं थी उन्हें आसपास के इलाकों से व्यापार के जरिए प्राप्त कर लिया जाता था। जैसे भारत में जो परंपरागत गांव हैं वहां हर प्रकार की जातियों का समावेश मिलता है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इन जातियों के हाथ में ही उत्पादन होता था और उन्हें गांव में बसाकर रखा जाता था। आज इक्कीसवीं सदी में ये बातें किसी कल्पनालोक की लग सकती हैं लेकिन आज भी ऐसे ग्राम्य जीवन में यह अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएगी जहां शहरी बाजार का प्रवेश नहीं हुआ है। भारत के गांवों में उपयोग की सारी जरूरत गांव में ही निर्मित करने पर कितना जोर रहता था इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि शीशा, पारा, लोहा जैसी धातुएं निर्मित करने की तकनीकी गांवों के पास थी और गांव गांव में इसके जानकार मिल जाते थे।

धीरे धीरे सारा उत्पादन तंत्र गांव के हाथ से निकलकर बड़े कारोबारियों के पास चला गया और जातियां अपना उत्पादन छोड़कर जातिवादी बहस और आरक्षण की लाइन में

जा खड़ी हुई। यूरोप के औद्योगीकरण ने जिस तरह से पूंजी और उत्पादन के केन्द्रीकरण का रास्ता तैयार किया था, भारत भी उस रास्ते पर आने से कब तक बच सकता था? पहले सरकार नियंत्रित उत्पादन तंत्र और बाद में मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था ने भारत के गांवों से उनकी सामान्य जरूरत का उत्पादन भी उनसे छीन लिया। अब लोगों के विकास से अधिक जोर पूंजी के विकास पर है। आज का जो विकास है मनुष्य के रोजगार की बजाय पूंजी और मशीनरी के रोजगार की चिंता ज्यादा करता है। पूंजी और मशीनरी को काम मिलना जरूरी है, इसके लिए भले ही मनुष्य को खाली हाथ घर बैठना पड़े। पूंजी और मशीन ने मानों मनुष्य के खिलाफ ही आपस में हाथ मिला लिया है।

ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ता है लेकिन बेरोजगारी भी उसी अनुपात में बढ़ती है। जो पूंजीवाद के पैरोकार हैं वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष रोजगार भले घटता है लेकिन परोक्ष रोजगार बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे लोग ये बात छिपा लेते हैं कि तकनीकी, मशीनरी और पूंजी के तालमेल से जो अर्थव्यवस्था निर्मित हो रही है उसमें 100 रोजगार जाता है तो केवल दस नया पैदा होता है। बाकी के नब्बे जो उनकी भाषा में अनस्किल्ड कह दिए जाते हैं उनके लिए इस अर्थव्यवस्था में क्या है?

इसका कोई जवाब किसी पूंजीवादी के पास नहीं होता। सरकारों के पास भी कोई जवाब नहीं है। सरकारों के सामने आधुनिक होने की चुनौती है और केन्द्र सरकार को दुनिया के देशों से कंपीटीशन भी करना है। क्या कोई देश तकनीकी को नकारकर आज के विश्व में टिका रह सकता है? इसलिए सरकार भी ऐसी नीतियों को बढ़ावा देती है जिससे पूंजी और उत्पादन का केन्द्रीकरण हो तथा उसकी आमदनी बढ़े।

लेकिन इसमें सबसे बड़ा संकट बाजार से उठने वाली मांग को लेकर पैदा होता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में बड़ी जनसंख्या के पास क्रयशक्ति ही नहीं बची तो उस अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा? भारत को ही देखें तो यहां 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का बड़ा शोर मचाया जाता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन उत्पादन तंत्र के केन्द्रीकरण से ये लक्ष्य प्राप्त भी हो गया तो भारत के लिए किस काम का होगा जब बड़ी जनसंख्या इसके लाभ से ही वंचित रहेगी?

आम चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा ईडी

नरेंद्र नाथ

करप्शन के आरोप में विपक्षी दलों के कई नेताओं पर जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की, अब वह राजनीतिक घमासान में बदल चुकी है। विपक्षी दल इसे बीजेपी की अगुआई वाली नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी किसी तरह से झुकने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर, 2024 लोकसभा चुनाव में जांच एजेंसियों की कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि विपक्ष इस पर एकजुट दिख रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सका, वह प्रवर्तन निदेशालय ने कर दिया। उनका इशारा भ्रष्टाचार के आरोपी विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर उस खेमे में बदले राजनीतिक समीकरणों पर था। प्रधानमंत्री के इस बयान का मतलब यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने अब सड़क पर उतरकर संकेत दे दिया है कि वे भी इन आरोपों का आक्रामक रूप से जवाब देंगे। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में जबसे केंद्र में बीजेपी सरकार आई, तब से राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंस ईडी के इस्तेमाल में चार गुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अभी तक इस जांच एजेंसी के दायरे में 125 नेता आए हैं, जिनमें 117 विपक्षी दलों से हैं। इसका मतलब यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने जिन मामलों में जांच शुरू की, उनमें से 95 फीसदी से अधिक विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ थे। वैसे, इस रिपोर्ट को लेकर भी विवाद हुआ। इसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हो गया। फिर जब एक संशोधन के जरिए ईडी को असीमित अधिकार दिए गए तो इस मामले पर भी विपक्ष एक हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में सभी राजनीतिक दल मिलकर इस संशोधन के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी में हैं। विपक्ष को यह भी लगता है कि बीजेपी का यह दांव इस बार निशाने पर नहीं लगेगा। उसका तर्क है कि हाल में जिस तरह से उसके नेताओं के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई हुई है, उससे न सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि जांच एजेंसियों की भी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए विपक्षी दल जांच एजेंसियों पर भी सीधे हमला कर रहे हैं। वैसे, एक वर्ग का मानना है कि जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं पर जिस तरह से एक के बाद लगातार हमला किया, उसी ने इस नैरेटिव को बनाने में विपक्ष की मदद की। नीतीश कुमार जैसे नेता जो अमूमन करप्शन जैसे मामलों पर किसी के बचाव में नहीं दिखते थे, उन्होंने भी इन एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। याद करें, 2017 में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद ही उन्होंने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था। लेकिन इस बार जब तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर छापे पड़े, तो वह उनके साथ खड़े दिखे। विपक्षी दल बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अडाणी मुद्दे को भी उछाल रहे हैं। उनका तर्क है कि इस मामले के सामने आने के बाद ईडी ने कारोबारी समूह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वे यह सवाल भी कर रहे हैं कि पिछले आठ वर्षों में जांच एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई में कोर्ट में आरोप सही साबित करने में पूरी तरह विफल रहीं। विपक्षी दलों का यह भी तर्क है कि आम लोगों के सामने अभी महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। उन्हें लगता है कि अगर वे इन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे तो न सिर्फ लोगों का साथ उन्हें मिलेगा बल्कि करप्शन के नाम पर होने वाली कार्रवाई से उल्टे उन्हें सहानुभूति मिलेगी। उधर, बीजेपी भी इस पिच पर लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। उसका तर्क है कि पार्टी को जनादेश करप्शन के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई के लिए मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंच से इस आशय की बात कह चुके हैं।

संसद में हंगामा लोकतंत्र का अनादर

डॉ. आशीष वशिष्ठ

संसद का मौजूदा बजट सत्र का पहला भाग हंगामे की भेंट चढ़ गया। उम्मीद थी कि होली के बाद बजट सत्र का दूसरा भाग लोकतांत्रिक ढंग से संचालित हो पाएगा। लेकिन फिलवक्त बजट सत्र के दूसरे भाग का हश्र भी पहले भाग जैसा होता दिख रहा है। पिछले कई वर्षों से संसद का सत्र शुरु तो बड़ी गर्मजोशी के साथ होता है मगर खत्म जनता के पैसे की बर्बादी के साथ होता है। बजट के पहले सत्र में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने अडाणी मामले को लेकर संसद का काम ठप किया। तो वहीं दूसरे भाग में विपक्ष अडाणी मामले पर जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के गठन की मांग को लेकर अड़ा है। तो वहीं सत्ता पक्ष के हाथ भी विपक्ष को घेरने का मुद्दा लग गया है। दरअसल, हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उन्हीं से सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए कहा था कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता। इसे लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के साथ देश का भी अपमान किया है इसलिए उनको क्षमा याचना करना चाहिए जिस पर कांग्रेस का पलटवार है कि विदेशों में राष्ट्रीय मुद्दों पर आलोचना की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने की इसलिए वे माफी मांगें।

दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। सत्ताधारी योद्धा झुकने को राजी हैं और न ही विपक्ष के महारथी। बजट सत्र में बजट पर चर्चा को छोड़कर बाकी सब हो रहा है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। अगले वित्त वर्ष का बजट 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली सरकार द्वारा पेश किया जावेगा। चुनावी वर्ष के मद्देनजर सत्तापक्ष ने बजट को लोक लुभावन बनाने की कोशिश की जबकि विपक्ष ने शुरुआती प्रतिक्रिया में ही उसे जनविरोधी बता दिया था। बजट का विस्तृत अध्ययन करने सत्र के बीच अवकाश भी दिया गया किंतु दूसरा चरण शुरू हुए तीन दिन बीत जाने पर भी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने की जरूरत किसी को महसूस नहीं हो रही।

डॉ. लोहिया आम जनता को मुल्क के मालिकों कहकर संबोधित किया करते थे किंतु आजकल इस संबोधन को हमारे सांसदों ने एक तरह से चुरा लिया है और जनता की जगह वे खुद को देश का मालिक समझ बैठे हैं। तभी तो सदन में हंगामा करते हुए लोकतंत्र का मजाक बनाने के बाद भी वे जनता के बीच जाने से नहीं डरते। ये स्थिति वाकई शोचनीय है। जब सदन को चलना ही नहीं है तब उसके संचालन पर प्रतिदिन करोड़ों का खर्च क्यों किया जाए ये सवाल उठना स्वाभाविक है। विदेश में जाकर लोकतंत्र का अपमान तो बाद की बात है लेकिन हमारे सांसद लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर जिस उद्दंडता और अशालीनता का परिचय दे रहे हैं वह ज्यादा बड़ा अपमान है।

संसद में एक घंटे की कार्यवाही पर कितना खर्च होता है। करीब 1.5 करोड़ रुपया यानि हर मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपया। ऐसे में स्वयं इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों में होने वाले बॉयकाट और हंगामे से जनता का कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो संसद में सालभर के तीन सत्रों में छह से सात काम के होते हैं। इनमें भी अगर अवकाश और सप्ताहांत के दिनों को निकाल दें तो दो से तीन महीने और कम हो जाते हैं। इस लिहाज से साल भर में वास्तविक काम के दिन 70-80 ही होते हैं, लेकिन इतने दिन भी संसद चल नहीं पाती। 1982 ही एकमात्र ऐसा साल था जब हमारी संसद 80 दिन चल पाई थी। संसदीय आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2016 के शीत कालीन सत्र के दौरान करीब 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे। इस दौरान करीब 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिसमें 138 करोड़ रुपये संसद चलाने का खर्च और 6 करोड़ रुपये सांसदों के वेतन, भत्ते और आवास का खर्च शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों के बजट सत्रों से तुलना की जाए तो आमतौर पर बजट सत्र में बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित घंटों के करीब 20 फीसद या 33 घंटे बहस होती है। वर्ष 2018 के बजट सत्र में कुल 21 प्रतिशत (लोकसभा) और 31 प्रतिशत (राज्यसभा) में काम हुआ। आंकड़ों के मुताबिक 2010 का शीतकालीन सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से सबसे खराब सत्र रहा था। इसके बाद 2013 और 2016 के संसद सत्रों का नंबर आता है। 2010-2014 के बीच संसद के 900 घंटे बर्बाद हुए, तो सोचिए कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा।

इस सब पर विडंबना यह है कि विपक्ष हो या फिर सरकार, किसी को भी चिंता नहीं है कि देश की जनता का पैसा किस तरह बर्बाद किए जा रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी ने संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी और अब वहीं काम कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है। प्रश्न यही है कि देश की जनता की इतनी फिक्र करने वाली राजनीतिक पार्टियां इतनी आसानी से जनता का पैसा कैसे बर्बाद कर देती हैं? संसद में हंगामा और उसे ठप कर देना तो हमारे देश के राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का हिस्सा और परंपरा बन गया है।

सदन में जारी हंगामे को देखकर अब जनता भी परेशान हो चुकी है और वह चाहती है कि उनका पैसा बर्बाद ना हो और सभी पार्टियों के नेता सदन की कार्रवाई में शांति से भाग लें। सदन अपने नियमों और गरिमा के साथ चले जिससे उसे देखने वाली जनता का नेताओं पर विश्वास बना रहें। सदन में हंगामा करने से नेता अपनी खुद की प्रतिष्ठा खो रहे हैं। तमाम दलों के नेता वेल तक पहुंच जा रहे हैं और स्पीकर पर पेपर फेंकते हैं। सदन में उपस्थित सभी नेताओं को माननीय कहकर पुकारा जाता है लेकिन सदन में हो रहे बर्ताव को देखते हुए क्या उन्हें माननीय कहना ठीक है?

माननीयों के इसी आचरण के चलते आम जनता अक्सर संसद की कार्यवाही और गंभीरता से ध्यान नहीं देती। लेकिन, यह एक बड़ा मुद्दा है। जनता को अब सोचने की जरूरत है कि उनके चुने हुए नेता उनकी बातें, समस्या का हल निकाल पर रहे हैं या नहीं। जनता के चुने हुए नेता उनकी बातें संसद में उठा पा रहे हैं या नहीं। संसद का कोई भी सत्र होगा, वो आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यहीं पर आम जनता के खाने से लेकर जिंदगी जीने तक सभी बातों का मोल लगाया जाता है। सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों पर विपक्षी दलों का हंगामा करना आम जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। संसद में आम जनता की भलाई के लिए फैसले लिए जाते हैं। लेकिन हर बार विपक्षी दलों को का हंगामा करते हुए कार्रवाई को स्थगित करना आम जनता के लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसलिए अब जनता को ही बड़े सोच विचार करते हुए अपने नेता का चुनाव करना होगा ताकि उनकी जेब और ढीली ना हो। अडाणी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच समिति बना दिए जाने के बाद अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग का कोई औचित्य नहीं रह गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी माफी मांगेंगे इसकी संभावना न के बराबर है। ऐसे में देश की जनता के लिए चिंता का विषय है कि उससे जुड़ी समस्याओं एवं राष्ट्रीय महत्व के शेष विषयों पर विचार इस सत्र में होगा भी या नहीं? संसद में हर रोज होने वाले हंगामे से देश के ज्यादातर लोग निराश हैं। सियासी बयानबाजियों के बीच आखिर संसद में काम कब होगा, कोई नहीं जानता।

प्रसंग

दानवीरता

धर्मान्ध और पितृद्रोही औरंगजेब जब अपने पिता शाहजहाँ को कैद में डालकर बादशाह बन बैठा तो उसने अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए अपने सगे भाइयों शुजा और मुराद को मौत के घाट उतार दिया। फिर सल्तनत के उत्तराधिकारी बड़े भाई दारा को गिरफ्तार कर, एक बूढ़ी हथिनी की पीठ पर उसे बिठा करके दिल्ली के मुख्य-मुख्य बाजारों में घुमाया। दोपहर की कड़ी धूप, हथिनी की नंगी पीठ और कैदी का वेश ! दारा को सहस्र बिच्छुओं के डंक से भी अधिक पीड़ा हो रही थी। उसे देखने के लिए भारी जनसमूह सड़कों पर एकत्रित हो गया था। दारा नीची नजर किये बैठा था कि इतने में आवाज आयी, दारा, जब भी तू निकलता था, खैरात करता हुआ निकलता था। मगर क्या आज मैं उस सखावत की उम्मीद न करूँ ?

दारा ने नेत्र उठाये और उस ओर देखा। लंगोटी पहने एक फकीर खड़ा था। उसने झट से अपने कन्धे पर पड़ा दुपट्टा उसकी तरफ फेंक दिया और फिर सिर नीचा कर लिया। फकीर दारा जिन्दाबाद के नारे लगाता नाचने लगा और प्रजा उसके साधुवाद पर आँसू बहाने लगी।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

2000 उगांडा में प्रलय दिवस सम्प्रदाय के 230 सदस्यों ने आत्मदाह किया।
2005 अदालत के आदेश के अनुसार, दिमागी क्षति का सामना करने वाली एक अमेरिकन महिला टेरी शियावो की फीडिंग ट्यूब को टोथर पति के अनुरोध पर हटा दिया गया था, जो इच्छामृत्यु पर दुनिया भर में बहस को बढ़ावा दे रहा था।
2006 संयुक्त राष्ट्र ने %मानवाधिकार परिषद% के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया।
2007 पाकिस्तान के क्रिकेट कोच बॉब वूल्मर किंग्सटन में होटल के बाथरुम में मृत पाए गए।
2010 ओरिडेन हिस्टोरियन कमीशन द्वारा 5 साल के शोध के बाद 1945 में ऑर्डन बम विस्फोट की रिपोर्ट।
2011 लीबिया पर कोई फ्लाई ज़ोन नहीं लगाए जाने के बाद, इसकी सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा की, इन 25 नागरिकों को मिसराता में संलग्न किया गया था।
2012 जर्मनी की संघीय सभा ने एफआरजी के अध्यक्ष के रूप में जोआचिन गौक को चुना।
2013 अल्फ्रेड ज़ेरेब, रोमन कैथोलिक चर्च के मानद प्रीलेट को पोप फ्रांसिस ने अपने निजी सचिव बनने के लिए चुना है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

मैत्रेय्युपनिषद् (भाग-05)

गतांक से आगे...

जिस मनुष्य को समस्त एषणाएँ इच्छायें वमन किये हुए (उगले हुए) आहार के समान लगती हैं और जिसने शरीर की ममता त्याग दी है, उसको संन्यास का अधिकार है। जब सभी वस्तुओं से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान् मनुष्य को संन्यास धर्म ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता है।

जो मनुष्य द्रव्य (धन) के, अन्न के, वस्त्रों के अथवा ख्याति के लोभ में संन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है, वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तत्त्व का चिन्तन ही उत्तम (श्रेष्ठ) है, शास्त्र का चिन्तन मध्यम है, मन्त्रों का चिन्तन (साधना) अधम है और तीर्थों में भ्रमण करना अधम से भी अधम है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य शाखा के अग्र भाग में प्रतिबिम्ब के रूप में दिखाई देने वाले फल का रसास्वादन कर आनन्द प्राप्त करना चाहे, उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म का आनन्द पाने की व्यर्थ कल्पना करता है।

जो संन्यासी मुक्त हो चुका है, वह वैराग्य रूपी पिता को श्रद्धा रूपी पत्नी को और ज्ञान रूपी पुत्र को न छोड़ते हुए अन्त:करण में स्थित अद्वैतभावना का आनन्दमय रूप में चिन्तन करे। जो (मनुष्य) धन में बड़ा है, जो आयु में बड़ा है अथवा जो विद्या में बड़ा है, वे सब अनुभव में बड़े के समक्ष नौकर अथवा शिष्य की भाँति ही हैं। जो माया के प्रभाव से मूढ़ चित्त वाले होकर के मैं रूपी आत्मा को सम्यक् रूप से नहीं जानते, वे यदि बुद्धिमान् भी हों, तो कौए की भाँति अभागे पेट को भरने के लिए जहाँ-तहाँ मारे-मारे फिरते हैं। प्रस्तर खण्ड, स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियों की पूजा, मोक्ष की इच्छा वाले को पुन: जन्म एवं भोग प्राप्त कराने वाली होती है। इस कारण पुन: जन्म न ग्रहण करना पड़े, इस उद्देश्य से संन्यासी को इस प्रकार बाह्य जगत् की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही (आत्मा की पूजा करनी चाहिए। समुद्र में रखा हुआ घड़ा अन्दर और बाहर जल से पूर्ण है तथा बाहर शून्य में स्थित घड़ा अन्दर और बाहर खाली ही है। आप ग्रहण करने वाले न बनें। इसी तरह से ग्रहण करने योग्य विषयरूप भी न बनें। इस प्रकार की सभी कल्पनाओं का त्याग करके शेष जो कुछ भी रहे, उसी में तन्मय रहें। द्रष्टा, दृश्य एवं दर्शन को वासना के साथ ही त्याग करके, जिसमें से दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता है, उस आत्मा का ही तुम भजन करो। सभी संकल्प जिसमें शान्त हो गये हैं, जागृति तथा निद्रा जिससे परे हो गयी है, ऐसी जो प्रस्तर खण्ड की भाँति (दृढ़ एवं निश्चेष्ट) अवस्था है, वही चरम स्वरूप की अवस्था है।

क्रमश:...

आयुध निर्माण दिवस

ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री डे अर्थात आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को पूरे भारत भर में मनाया जाता है। कोसीपुर, कोलकाता में स्थित भारत के सबसे पुराने आयुध निर्माणी फैक्ट्री का उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू किया गया था। ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, ऑर्डिनेन्स पैराशूट फैक्ट्री और ऑर्डिनेन्स उपकरण फैक्टरी इस दिन को महान धूमधाम के साथ आयुध कारखानों में मनाते हैं जिसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारी विभिन्न संगठित आयोजनों में भाग लेते हैं। इस अवसर पर पूरे देश में जगह जगह रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी व विभिन्न आयु वर्ग में आयुध दौड़ का आयोजन किया जाता है।

आयुध निर्माण दिवस के अवसर को भारत के सशस्त्र बलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के माध्यम से आयुध मंडल के समर्पण की पुष्टि के लिए एक याद के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आयुध कारखानों के कर्मचारियों को उनके कार्य उत्कृष्टता के लिए याद किया जाता है।

भारतीय आयुध निर्माणियाँ एक भव्य औद्योगिक संरचना हैं जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करती हैं। भारतीय आयुध निर्माणियाँ का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वह 41 निर्माणियों, 9 प्रशिक्षण संस्थान, 3 क्षेत्रीय विपणन केन्द्र ओर 4 क्षेत्रीय संरक्षा नियंत्रणालयों का समूह है। आज आयुध निर्माणी बोर्ड भारतवर्ष में 41 निर्माणियों में फैली है।

प्रौद्योगिकी सामर्थ्यताओं के साथ एक बृहत् और परिवर्तनीय उत्पादन आधार तथा अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं को प्रदान करना इस दिवस का उद्श्य है। कुशल और पेशेवर अर्हता प्राप्त जन शक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों का बृहत् भंडार है। गुणवता मानकों का सख्त पालन करना है। आवश्यकता आधारित परिष्करण एवं सुधार के लिए मौलिक एवं अनुकूलित अनुसंधान एवं विकास को महत्व देना इस दिवस का उद्देश्य है।

ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ बोर्ड भारत के सशस्त्र बलों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए आयुध निर्माण दिवस को महत्व देते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। संगठन न केवल विभिन्न सशस्त्र बलों के लिए हथियारों की आपूर्ति करता है बल्कि यह ग्राहकों की अन्य इच्छाओं को भी पूरा करता है जिसमें गोला-बारूद, हथियार, माइन संरक्षित वाहन, बुलेट प्रूफ वाहन, कपड़े आदि के संबंध में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल हैं।

पाकिस्तान के लिए आपदा साबित हुए इमरान

मरिआना बाबर

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने एक लेख का शीर्षक देखा, जिसमें लिखा था-हमें अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर संकट का हल ढूंढ़ने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, और अचानक मैंने सोचा, क्या होगा अगर यहां अमेरिका और मैक्सिको की जगह भारत और पाकिस्तान को रख दिया जाए। क्या हमें भी दोनों देशों के बीच इस %युद्ध नहीं% वाले परिदृश्य को नया नियम मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और उस संकट को हल करने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए, जिसका हम दशकों से सामना कर रहे हैं? खैर, इस विषय पर फिर कभी लिखूंगी, लेकिन पाकिस्तान में हर कोई (आम जनता, जो भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर नजर रखती है और सरकार में शामिल लोग भी) इस बात से हैरान है कि क्यों मोदी सरकार इस साल की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की अनदेखी कर रही है, जो सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए हालिया समझौतों से संबंधित है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के सऊदी अरब और ईरान, दोनों के साथ बहुत अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते हैं। मैंने इस विषय पर भारतीय मीडिया में प्रकाशित कुछ संपादकीय देखे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नई दिल्ली द्वारा स्वागत या निंदा से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं थी। पाकिस्तान ने चीन की मध्यस्थता में हुए इस समझौते का स्वागत किया है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच जारी तनाव पाकिस्तान की धरती पर शिया और सुन्नी के

बीच संघर्ष में दिखा, जहां ये दोनों देश अलग-अलग गुटों का समर्थन कर एक तीसरे देश की धरती पर लड़े। शिया समुदाय को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन पर चरमपंथियों और यहां तक कि जिहादियों, विशेष रूप से बलूचिस्तान में हजराजात समुदाय द्वारा हमला किया जाता है, जहां सामूहिक हत्याएं हुई हैं।

सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति और बेहतर द्विपक्षीय संबंधों का असर तुरंत पाकिस्तान पर दिखेगा, जहां उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तानी समूहों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन अमर उजाला के पाठकों को पिछले दो दिनों से पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रम में ज्यादा दिलचस्पी होगी, जहां पड़ोसी मुल्क की प्रांतीय राजधानी लाहौर के पॉश और सुरुचिपूर्ण इलाके में युद्ध जैसा माहौल दिखता है, जहां से कुछ बहुत ही बदसूरत दृश्य सामने आ रहे हैं। इस बीच, बाकी लाहौर हमेशा की तरह शांत और सामान्य है, यहां तक कि पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच भी लाहौर के किसी अन्य हिस्से में बड़ी भीड़ खींच रहा है।

लाहौर के जमान पार्क इलाके में तहरीक-ए इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान का घर है, जो कई दशक पहले उन्हें अपने भाई-बहनों के साथ पिता से विरासत में मिला था। यह उच्च मध्यवर्गीय पंजाबी परिवार का बहुत ही सामान्य घर था। लेकिन जब इमरान खान मुल्क के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी तीसरी बीवी बेगम बुशरा ने घर के भीतरी और बाहरी हिस्से में इतनी मरम्मत कराई कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यह वही पुराना मामूली बंगला है। अब इसका डिजाइन ज्यादा आलीशान है और भीतरी कमरे शाही महल जैसे दिखते हैं। निस्संदेह उन पर बड़ी रकम खर्च की गई है। इन दिनों यह इलाका इसलिए युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने कानून के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। उन्हें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट द्वारा तलब किया गया है, लेकिन वह बहाना बनाते हैं और अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं होते हैं।

आखिरकार अदालतों को इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी वारंट के साथ भेजना पड़ा, लेकिन इमरान खान इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने और पीटीआई के अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर लोगों का आह्वान किया और देखते ही देखते डंडों, लाठियों, गुलेल और पत्थरों से लैस हजारों समर्थक पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मैंने जिस तरह से इन समर्थकों को पुलिस और रेंजरों के साथ संघर्ष करते हुए देखा, यह साफ था कि ये सामान्य समर्थक नहीं थे, बल्कि वे लोग थे, जो गुरिल्ला युद्ध में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। वे नकाबपोश थे और उन्होंने पुलिस के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। उनके पास पेट्रोल बम थे और उन्होंने सरकारी एवं निजी वाहनों को नष्ट कर दिया। यहां तक कि जिन वाहनों में पुलिस और रेंजर्स बैठे थे, उन्होंने उस पर भी पेट्रोल बम फेंके, जिसके चलते उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा। गनीमत रही कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किसी तरह की हवाई फायरिंग नहीं हुई।

वास्तव में राज्य पुलिस तंत्र की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब पता चला है कि गिलगिट-बाल्टिस्तान की पुलिस इमरान खान के समर्थकों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अवैध रूप से लाहौर आई थी। गिलगिट-बाल्टिस्तान पुलिस प्रमुख का तबादला कर दिया गया है और अब जांच से ही पता चलेगा कि ऐसा खतरनाक कदम उठाया गया या नहीं तथा उठाया गया, तो क्यों। मगर जो सबसे जरूरी सवाल है, वह कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर किन वजहों से इमरान खान अपने समर्थकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वह खुद छिपे हुए हैं और अन्य नेताओं की तरह अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा के उस विफल प्रयोग में निहित है, जिसके तहत उन्होंने पिछले आम चुनाव में धांधली करके और इमरान खान को केंद्र में लाकर उनकी गठबंधन सरकार बनवाई थी। इमरान खान पाकिस्तान के लिए आपदा साबित हुए, क्योंकि उन्होंने दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ तनाव बढ़ाया और पाकिस्तान का शासन करने में असमर्थ रहे।

गांधी आज

धार्मिक दृष्टि

हिन्दू धर्म में गो-पालन को धार्मिक महत्त्व दिया गया है और गो- वध महापाप माना गया है तथा गो-रक्षा राजाओं और वैश्यों का एक विशेष कर्त्तव्य बताया गया है। इसलिए इस कार्य के निमित्त लाखों रुपए दान किए जाते हैं। पर यह सब होते हुए भी, उचित दृष्टि के अभाव से हिन्दुस्तान के पशुओं की दशा गो-भक्षक देशों से भी अधिक दयनीय है। गो-पालन-संबंधी धार्मिक दृष्टि में नीचे लिखे अनुसार विकास होने की आवश्यकता है-

(अ) अपंग और निर्बल पशुओं का पालन करना मात्र गो-पालन का क्षेत्र नहीं है, गाय और बैलों की नस्ल सुधारना, गाय को अधिक सत्त्व वाली और अधिक दूध देनेवाली बनाना तथा बैल की किस्म सुधारना भी गो-पालन-धर्म में सम्मिलित है।

(आ) अत: पींजरापोल ऐसी आदर्श गोशालाएं होने चाहिए जो लोगों को गो-पालन का पदार्थ-पाठ दे सकें-उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन सकें। गायों के रखने खिलाने के स्थान, उन्हें घास, दाना आदि देने के तरीके और नतीजों का लेखा रखने में शास्त्रीय सावधानता और शास्त्रीय विधि से काम करने का अभ्यास प्रकट होना चाहिए।

(इ) पींजरापोल को इस दृष्टि से अच्छे सांड पालने चाहिए कि पशुओं

की नस्ल सुधारने में गाँव के लोग उनका उपयोग कर सकें।

(ई) पींजरापोल में चर्मालय-विभाग भी होना चाहिए और मरे ढोरों के हाड़-मांस तथा चमड़े के धंधे के प्रति घृणा दृष्टि रखने के बदले कर्त्तव्य-दृष्टि होनी चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि जो मालिक मरे पशुओं के हाड़-माँस और चमड़े का उपयोग नहीं होने देता वह उनकी हत्या को उत्तेजन देता है, इसलिए जीवदया धर्मी को उचित है कि वह मरे पशुओं के ही हाड़-माँस और चमड़े का सदुपयोग करने का आग्रह रखे।

संक्षिप्त समाचार

अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होने युवाओं के लिए सुनहरा मौका

बिलासपुर। अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होकर भारतीय सेना में सेवा देने के लिए युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च को है। इस संबंध में जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में ऑनलाईन कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद द्वितीय चरण में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से अग्निवीर सामान्य डयूटी (ऑल आर्मी), अग्निवीर सामान्य डयूटी (अनुसूचित जनजाति) ऑल आर्मी, अग्निवीर लिपिक (क्लर्क/स्टोर कीपर) (ऑल आर्मी), अग्निवीर टेक्निकल (ऑल आर्मी), अग्निवीर ट्रेडमेन 10वीं उत्तीर्ण (ऑल आर्मी) एवं अग्निवीर ट्रेडमेन 8वीं उत्तीर्ण (ऑल आर्मी) के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 08वीं, 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण युवा आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर में चयन होने के बाद उन्हें प्रथम वर्ष 30 हजार एवं भत्ता, द्वितीय वर्ष 33 हजार एवं भत्ता, तृतीय वर्ष 36 हजार 500 एवं भत्ता तथा चतुर्थ वर्ष 40 हजार वेतन एवं भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही चार वर्ष पश्चात् अग्निवीर को लगभग 10 लाख ब्याज सहित सेवा निधि पैकेज के रूप में दिया जायेगा, जो आयकर छूट योग्य रहेगा। ऐसे अग्निवीर जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें चार साल की सेवा पश्चात् 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने भक्त माता कर्मा जयंती की दी शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने माता कर्मा से प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने भक्त माता कर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में भक्त माता कर्मा जयंती का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर साहू समाज द्वारा विशेष रूप से अन्य समाजों के साथ शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाती है और धार्मिक-सामाजिक आयोजन होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने भक्त माता कर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की है कि माता कर्मा हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।

कस्टम मिलिंग के लिए 105.55 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की कुशल प्रबंधन के कारण अब तक कस्टम मिलिंग के लिए 105.55 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है, जबकि 107.53 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की सफलतापूर्वक खरीदी की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए सीधे उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव शुरू किया गया था, जिसके चलते राज्य सरकार को परिवहन व्यय में काफी कमी आयी है। इसके साथ ही धान खरीदी के बाद धान उठाव की लंबी प्रक्रिया से भी निजात मिली है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 23 लाख 42 हजार से अधिक किसानों से 31 जनवरी 2023 तक 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। किसानों को धान खरीदी के एवज में 22 हजार 67 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

राशन कार्डधारियों को अप्रैल और मई माह का राशन मिलेगा एक साथ

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र राशन कार्डधारियों को माह अप्रैल और मई का राशन एक साथ प्रदान किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग के पश्चात् चावल उपार्जन के लिए गोदामों में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा पीडीएस एवं सार्वभौम पीडीएस के तहत प्रचलित सभी राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल और मई का चावल एक साथ वितरण करने का निर्णय लिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल और मई का राशन वितरण किए जाने हेतु खाद्यान्न का भंडारण उचित मूल्य दुकानों में समय पर किया जाए तथा अन्नवितरण पोर्टल में इस संबंध में माहवार वितरण दर्शाने के लिए आवश्यक व्यवस्था किया जाए। भंडारित खाद्यान्न की निगरानी समिति तथा खाद्य अधिकारियों के माध्यम से पुष्टि कराया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि दो माह के चावल वितरण संबंधी सूचना राशन कार्डधारियों को मुनादी और उचित मूल्य की दुकानों पर पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शित कर की जाए।

चरणदास महंत ने भक्त माता कर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश वासियों को भक्त माता कर्मा जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है।विस् अध्यक्ष डॉ. महंत ने कहा कि, भक्त माता कर्मा सेवा, त्याग, भक्ति एवं समर्पण की देवी तथा सर्व साहू तैली समाज की आराध्य देवी है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में तन-मन और धन से लगन पूर्वक लगे रहना, दीन-दुखियों के प्रति दया भावना रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा।

विकास की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़-बघेल

मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के लिए 13 हजार 325 करोड़ रूपए से अधिक राशि की अनुदान मांगें पारित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ऋण भार बजट का 17.9 प्रतिशत है, अन्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। आम जनता की सुविधा हेतु नए जिले, तहसीलें और अनुविभाग बनाए गए। भेंट-मुलाकात में आम जनता से सीधा संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निवारण हो रहा है। हमारी सरकार ने कई नवाचार किए हैं, इसके लिए नवाचार आयोग बना रहे हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में लोगों के विकास के लिए नई-नई योजनाओं तथा कार्यक्रमों का बेहतर ढंग से संचालन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ के नवाचारों की चर्चा करते हैं। नीति आयोग की बैठक में और व्यक्तिगत मुलाकातों में भी इसकी जरूर चर्चा

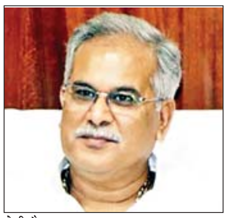

होती है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में दिनों-दिन अंडरग्राउंड वॉटर नीचे जा रहा था, इसे रोकने के लिए नरवा कार्यक्रम हमने शुरू किया। जिसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा है। नवीन पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, इसके लिए प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। राज्य में 1 नवम्बर 2004 से लागू की गई नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से समस्त शासकीय सेवकों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। इसके फलस्वरूप भविष्य में पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु गठित पेंशन निधि में निवेश के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 11 हजार 256 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना के तहत मार्च 2019 से दिसम्बर 2022 तक लगभग 42.20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 3453.17 करोड़ रूपए की तथा ग्रामीण औद्योगिक पार्क एवं 334 गौठानों के कनेक्शन को रियायत प्रदान की जा चुकी है। राज्य में 20 हजार 550 पंपों का विद्युतीकरण मार्च 2023 तक पूर्ण करने की योजना है। छत्तीसगढ़ में बिजली की कमी नहीं है, जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है, इसे ध्यान में रखकर नए उपकेंद्र खोलने की कार्य योजना बनाई जा रही है। राज्य शासन द्वारा 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार भयमुक्त वातावरण में स्वंत्रत होकर कार्य कर सके, इस दिशा में

भी हम प्रभावी तरीके से उपाय सुनिश्चित कर रहे हैं। पत्रकार साथियों के लिए अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण किया गया है। अधिमान्यता का कोटा दोगुना करने से अधिमान्य पत्रकारों की संख्या 400 से बढ़कर 600 तक पहुँच गई है। इसी तरह सम्मान निधि को 5000 से बढ़ाकर 10,000 रूपए की गयी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हित में पत्रकार गृह निर्माण ऋण ब्याज अनुदान योजना लायी गई है। जिससे पत्रकार साथियों के स्वयं के घर का सपना पूरा हो सके। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में गृह निर्माण ऋण ब्याज अनुदान के लिए 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ के हित में कोई बात है तो, इसके लिए लड़ना भी पड़े तो, हम पीछे नहीं रहेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत किया, उसे सजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रूपए का चिट-फंड पकड़ाया, दोषी लोग जेल में हैं, उनकी संपत्तियां नीलाम कर पीड़ित लोगों को राशि लौटाने का काम किए हैं।

अनिला भेंडिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला कर्मियों का किया सम्मान

■ आंगनबाड़ी केन्द्रों को गैस-चूल्हा और महिला समूह को बांटा गया ऋण

बलौदाबाजार-भाटापारा। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने गुरूवार को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखण्ड के ग्राम हथबंद में आयोजित वृहद महिला सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 30 से अधिक महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान किया। उन्होनें 5 आंगनबाड़ी केन्द्रों को गैस-चूल्हा तथा महिला कोष से विभिन्न स्व-सहायता समूह को 11 लाख रूपये से अधिक का ऋण वितरण भी किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्य सभा की पूर्व सांसद श्रीमती छाया वर्मा, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विद्याभूषण शुक्ल, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा, पूर्व विधायक बलौदाबाजार श्री जनक राम वर्मा, पूर्व विधायक दुर्ग श्रीमती प्रतिमा

चंद्राकर, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।श्रीमती भेंडिया ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाब हो रही हैं। महिलाएं खेती किसानी करने से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाकर विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से देश की सेवा कर रहीं है। राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों की शिक्षा, रोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से पात्र पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों की बैंक खातें में एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन सेंटरों के माध्यम से एक छत के नीचे महिलाओं को निःशुल्क विधिक चिकित्सा, परामर्श और आश्रय दिया जा रहा है। श्रीमती भेंडिया ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

प्रधानमंत्री वैश्विक आर्थिक विकास हेतु शांति के पक्षधर - राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज मैटस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रिसर्च कान्क्लेव 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दिया। इस सम्मेलन का विषय वैश्विक वितीय एवं आर्थिक परिवर्तन- विकास पर प्रभाव था। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए विश्व मे शांति स्थापित होना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहें युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति का मार्ग अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युद्ध केवल विनाश की ओर ले जाता है। यह मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल विश्व की वित्तीय व्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है और आम जनता को आर्थिक

बदहाली से गुजरना पड़ता है। इसलिए युद्ध और नरसंहार की कीमत पर किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इसे बातचीत के जरिए ही सुलझाने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। विश्व ने दो महायुद्ध और उसके दुष्परिणाम देखे हैं। इनसे दुनिया को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, चीन, जापान, और जर्मनी के बाद विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पांच ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना देखा था वह अब वास्तविक स्वरूप ले रहा है। भारत के लाखों वंचित वर्गों को बैंकिंग तंत्र से जोड़ा गया है और करोड़ों युवाओं को 20 लाख करोड़ से अधिक का मुद्रा ऋण बिना बैंक गारंटी स्वीकृत किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिचंदन ने स्मारिका का विमोचन किया। मैट्स विश्वविद्यालय की ओर से राज्यपाल को पुस्तक, शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सेमिनार मे विभिन्न राज्यों के शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्रीमती लुभा मुखर्जी, मैट्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया, कुलपति श्री के.पी.यादव, शिक्षाविद्, शोधकर्ता एवं विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

चार करोड़ की लागत से कोंडातराई उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए का नया ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत

रायपुर। प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अपनी पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के 132/33 कोडातराई उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए (मेगा वोल्ट एम्पीयर) क्षमता के ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत किया गया। प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल ने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। लगभग चार करोड़ की लागत से किए गए इस क्षमता वृद्धि से जिले के दो सौ से अधिक गाँवों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इससे वनवासी बहुल इस क्षेत्र के किसानों समेत आम ग्रामीणों को लाभ होगा। पॉवर कंपनी शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए उच्च दाब उपकेन्द्रों में स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा रही है। कोडातराई उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए की क्षमता वृद्धि के साथ प्रदेश की कुल पारेषण क्षमता बढ़कर 22658 एमव्हीए हो गई है। उच्चदाब ट्रांफार्मर के ऊर्जी करण

के अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री चंद्रशेखर सिंह, मुख्यअभियंता द्वय श्री के के भगत एवं श्रीमती के घाटे, अधीक्षण अभियंता सर्वश्री सी एम वाजपेई, वी.पी.पटेल,आर के अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता गुंजन शर्मा, जे पी सिदार, जी आर् जायसवाल, मोहित बंजारे, सहायक अभियंता श्री आर के राव, मोहन पैकरा, प्रेम उरांव, बजरंग विश्वकर्मा समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने भक्त माता कर्मा जयंती की दी शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने माता कर्मा से प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने भक्त माता कर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में भक्त माता कर्मा जयंती का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर साहू समाज द्वारा विशेष रूप से अन्य समाजों के साथ शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाती है और धार्मिक-सामाजिक आयोजन होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने भक्त माता कर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की है कि माता कर्मा हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।

चेटीचण्ड्र महोत्सव पर नगरीय क्षेत्रों में होगा अवकाश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित शदाणी दरबार तीर्थ में आयोजित संत राजाराम साहिब जी के 63वें वर्सी महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर चेटीचण्ड्र महोत्सव पर राज्य के नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में अवकाश की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शदाणी दरबार में संत राजाराम साहिब के 63वें वर्सी महोत्सव में शामिल होने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए लगभग 350 श्रद्धालुओं का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर शदाणी दरबार द्वारा 122 माताओं और बहनों को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने की व्यवस्था किए जाने पर प्रशंसा की। शदाणी दरबार में संत राजाराम साहिब जी के 63वें वर्सी महोत्सव का आयोजन 14 से 17 मार्च 2023 के बीच किया जा रहा है। शदाणी दरबार द्वारा पवित्र सरोपा भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर शदाणी दरबार पर आधारित फिल्म धुनेश्वर महादेव की सीडी का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज मूलतः व्यावसायिक समाज है, छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के कर्ज माफी तथा सर्वाधिक दाम में धान की खरीदी सहित कई ऐसे कार्य किए हैं, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इन कार्यों का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को मिला है। ग्राहकों की जेब में पैसा जाने से बाजार गुलजार हैं। पूरे देश में मंदी होने पर भी छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहा, यहां के बाजारों में रौनक बनी रही। शदाणी दरबार के पीठाधीश संतश्री डॉ. युधिष्ठिरलाल, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत स्वामी रामसुंदर दास, रायपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा, सिंधी अकादमी के अध्यक्ष श्री राम गिडलानी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

संघ की प्रतिनिधिसभा में स्वः को जागृत करने का संकल्प

छत्तीसगढ़ प्रांत में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य विस्तार तेज गति से हो रहा

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना ने पत्रकारों को संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. सक्सेना ने बताया कि, पानीपत, हरियाणा में संपन्न हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में देशभर से 34 संगठनों के 1474 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर

स्व:आधारित राष्ट्र के नवउत्थान के संकल्प लिया गया। प्रतिनिधि सभा में बताया गया कि देश के प्रत्येक भाग में संघ कार्य में वृद्धि हो रही है। 2025 में संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। वर्तमान में संघ 71355 स्थानों पर प्रत्यक्ष तौर पर कार्य कर समाज परिवर्तन के महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है। अगले एक वर्ष तक एक लाख स्थानों तक पहुंचना संघ का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रान्त में वर्तमान में संघ की शाखाएँ 1142 व साप्ताहिक मिलन 515 चल रहे हैं। आगामी मई माह में शुरू होनेवाले संघ के औपचारिक प्रशिक्षण संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष में 500, द्वितीय वर्ष में 100 व तृतीय वर्ष में 20 शिक्षार्थी भाग लेने का अनुमान है। अपने प्रान्त में गत मार्च 2022 के बाद हुए प्राथमिक शिक्षा वर्ग कुल 34 स्थानों पर सम्पन्न हुए जिसमें कुल 3192 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ प्रांत में कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता विकास वर्गों के माध्यम से नए कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा गतिविधियों के माध्यम से कुटुम्ब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण तथा नागरिक कर्तव्यबोध इन विषयों पर योजनाबद्ध रूप से कार्य हो रहा है। क्षेत्र का सामाजिक अध्ययन शाखाओं के द्वारा हो रहा है। रायपुर महानगर में सेवाकार्य हेतु 83 सेवाबस्ती चिन्हित कर उनसे से 32 सेवाबस्ती में सेवाकार्य प्रारम्भ हुए हैं। प्रान्त के अन्य 33 जिलों में सेवाकार्य हेतु 147 सेवाबस्ती चिन्हित कर उनमें से 125 सेवाबस्ती में सेवाकार्य प्रारम्भ हुए हैं। इन सेवाबस्तियों में संघ स्वयंसेवकों के सम्पर्क माध्यम से व समाज के सहयोग से अभावग्रस्त लोगों के बीच सेवा कार्य संचालित किया जा रहा है। पूरे देश में जिस प्रकार संघ कार्य बढ़ा है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रांत में भी कार्य विस्तार तेज गति से हो रहा है। सामाजिक सदभाव व समरसता के लिए कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सामाजिक चुनौती समरसता को केंद्रित कर गावों में, बस्तियों में समरसता सर्वेक्षण व सामाजिक अध्ययन कराया। कुछ चिन्हित स्थानों पर समन्वय व सदभाव बैठकों का आयोजन भी किया गया है। समाज जागरण हेतु संकल्प कार्यक्रम विद्यालय, महाविद्यालय, विभिन्न सामाजिक एवं सार्वजनिक संस्थानों में सम्पन्न हुए।

स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलनों के साथ 22 जिलों में जिला रोजगार सृजन केंद्रों का शुभारंभ किया गया।

पारित प्रस्ताव

वर्तमान समय देश को सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते देखना आनंद का विषय है। भारत की शक्ति, सामर्थ्य एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण काल में भी देश की आत्मनिर्भरता का संकल्प सुफल देने की स्थिति में आया है। देश के स्वाधीनता के अमृतकाल में भी कई गंभीर चुनौतियां हैं। इतिहास की परिस्थितियों से उत्पन्न विकृत एवं स्वार्थी मानसिकता वाले राष्ट्र घातक तत्वों की कुटिलता के कारण कई सामाजिक एवं राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मतांतरण के षड्यंत्रों से भी समाज संघर्ष कर रहा है। शताब्दी वर्ष के लक्ष्य के निमित्त कार्य विस्तार एवं गुणवत्ता के सार्थक प्रयासों के साथ साथ समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली, नागरिक कर्तव्य का जागरण जैसे समाज परिवर्तन के विविध आयामों को प्रभावी बनाना, वैचारिक विमर्श को राष्ट्रीय दिशा देना और समाज की सज्जन शक्ति का सही संचालन करना इन कार्यों में भी सफलता प्राप्त करना, इस लक्ष्य को लेकर हम बढ़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को मिला सुरक्षा कानून

कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

रायपुर। भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया. इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा कानून को हरी झंडी दे दी है. अब इस कानून को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. पत्रकार सुरक्षा कानून के अलावा सीएम भूपेश की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं.बघेल कैबिनेट का फैसला = मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर के समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक हुई है. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जिसमें छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के ड्राफ्ट को मंजूरी, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता–1959 में संशोधन, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा देने का अधिकार वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है. छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी देने के मकसद से लाया गया है.इसके तहत पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करना है. ताकि विषम परिस्थितियों में उनके ऊपर होने वाले हमलों को रोका जा सके. इस कानून के लागू हो जाने से मीडिया कर्मियों को प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी. अगर कोई मीडिया कर्मियों पर हमला करता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से वादा किया था कि वह प्रदेश में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लाएंगे. इसे अब भूपेश कैबिनेट से पास कर दिया गया है. विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है. अब देखना होगा कि क्या सरकार इसे इसी सत्र में सदन में प्रस्तुत करती है. इस पत्रकार सुरक्षा कानून में मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने के मकसद से उनका पंजीयन कराया जाएगा. इसे जोखिम प्रबंधन इकाई का नाम दिया गया है. छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की मान्यता से जुड़ी शर्तों को भी इस कानून के माध्यम से सरल बनाया जाएगा. इसके तहत राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कोटे को बढ़ाकर 600 तक किया गया है. पत्रकारों की सम्मान निधि में भी इजाफा किया गया है. इसे पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक किया गया है. शिक्षा व्यवस्था के लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था की गई. इसके साथ ही कई विधेयकों को मंजूरी दी गई. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक–2023 को पास किया गयाछत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति को मंजूरीछत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के वेतन भत्ते एवं पेंशन विधेयक–2023 के प्रारूप को अरूव किया गया.छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये की विश्व बैंक परियोजना को भी मंजूरी दी गईइसके साथ ही ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीतने वाली आकर्षी कश्यप को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति देने का फैसला कैबिनेट की मीटिंग में किया गया है.आकर्षि कश्यप पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के पद पर तैनात रहेंगी।

बैठक की महत्वपूर्ण निर्णय

- छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए, शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
- कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त कु. आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधायक अमितेश के अंग्रेजी में बोलने पर विस अध्यक्ष हुए नाराज

रायपुर। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए. शुक्ल ने गरियाबंद और देवभोग में चना सप्लाई में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया. इस दौरान शुक्ल खाद्य सामग्री के सप्लाई का प्रावधान अंग्रेजी में पढ़ने लगे. जिस पर कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि मंत्री जी समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे. इस पर अमितेश शुक्ला ने कहा कि मंत्री जी को काफी ज्ञान है, आप चिंता ना करें.पक्ष–विपक्ष के विधायकों ने ली एक दूसरे की चुटकी– इस बीच विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं, जो अंग्रेजी नहीं समझते. तो आप हिंदी में सवाल पूछें. इसके बाद अजय चंद्राकर ने कहा लखमा राज्यपाल के अभिभाषण में टेबल थपथपा रहे थे. जिस पर मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि वह तो अभिभाषण को पलटकर पढ़ रहे थे. लखमा को जितना ज्ञान है, आपको नहीं है.

ये आपकी व्यक्तिगत चर्चा नहीं है- इस बीच चरणदास महंत ने अमितेश शुक्ल से कहा कि जो सदन में चर्चा हो रही है. आपको ये व्यक्तिगत चर्चा नहीं, पूरे प्रदेशभर की चर्चा है. आपके भाषण का छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार होता है. इसके बाद अमितेश शुक्ल ने कहा कि आप कहते हैं, तो अंग्रेजी में नहीं बोलता हूं. पैकेजिंग में धांधली हुई है, एक सामान को गरियाबंद में फेल किया. देवभोग में उसे पास किया है. अमितेश शुक्ल के सवालों पर मंत्री अमरजीत भगत ने अंग्रेजी में मुस्कुराते हुए कहा कि एज यू हैव मेड ए स्पेसिफाइड कंप्लेंट कैन यू टेल द डिटेल टू मी. इसके बाद अमरजीत ने हिंदी में भी इस लाइन को बताते हुए कहा कि कोई भी आपके पास लिखित दस्तावेज हो, शिकायत हो, तो आप पेश कीजिए, मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा. शिकायत हमारे पास आई, हमने खराब सामान को रिजेक्ट किया.

अमितेश ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप- विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा कि मंत्री जी को अधिकारी सही जानकारी नहीं देते हैं.

बेबसी का इक समंदर दूर तक फैला हुआ....

दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी चर्चा में रही सीबीआई और बाद में ईडी ने दिल्ली सरकार की साल 2021 की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में ये गिरफ्तारी की है।इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताया है।पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के मंत्रियों और नेताओं को निशाना बना रही है जहाँ विपक्षी पार्टियाँ सरकार चला रही हैं।इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक ओर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पूरी तरह सक्रिय है।एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के नेताओं और कई नौकरशाहों को 2020 में हुए कोयले से जुड़े एक घोटाले के मामले में अक्टूबर 2022 से कुछ-कुछ दिनों के अंतराल पर पूछताछ के लिए समन जारी किया जा रहा है और कुछ की गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं।अभी कुछ आईएएस के बाद आईपीएस निशाने पर हैं?बीते कुछ महीनों से बार–बार ये बात विपक्ष और एक तबका दोहरा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को मोदी सरकार विपक्ष को काबू में करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।बीते साल मार्च में लोकसभा में दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि साल 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5346 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की गई लेकिन साल 2014 से लेकर 2022 के आठ वर्षों के बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने 3010 छापा मारा और लगभग एक लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। पिछले आठ सालों में राजनीतिक लोगों के ख़िलाफ़ ईडी के मामले चार गुना बढ़े हैं. साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जाँच ईडी कर रही है, इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं यानी 95 फ़ीसदी मामले विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ हैं।अब इसकी तुलना यूपीए के समय से करें तो 2004 से लेकर 2014 के दस सालों में 26 नेताओं की जाँच ईडी ने की इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे।

हालांकि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज केस की जानकारी देता हो %हम आम केस और राजनेताओं के केस को अलग–अलग तरह से नहीं देखते% ईडी की तरह सीबीआई के मुकदमों के आंकड़े देखें तो यूपीए के दस सालों में 72 राजनेता सीबीआई के स्कैनर में आए और उनमें से

43 नेता विपक्ष के थे यानी तकरीबन 60प्रतिशत...साल 2014 से लेकर 2022 तक एनडीए की सरकार में 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टी के थे यानी 95 फ़ीसदी विपक्ष के नेता हैं।

छग भाजपा के विधायक और टिकट

भाजपा के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान सामने आया है। उनके अनुसार चुनाव में हर राज्य का अपना अलग फार्मूला लागू होता है, यह जरूरी नहीं कि एक जहां जीते हैं, उस फार्मूले को दूसरे राज्य में लागू किया जाए।गुजरात और उत्तरप्रदेश की परिस्थितियां अलग थी और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग है।(उन्हें शायद यह याद नहीं है कि छग में तत्कालीन केंद्र सरकार में शामिल एक मंत्री सहित सभी सांसदों का टिकट काट दिया गया था) खैर वे कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जीतने योग्य उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने इशारा किया कि चुनाव में हार की संभावना वाले विधायकों का टिकट कट सकता है। छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन होगा इसका निर्णय न मैं कर सकता हूं न यहां की टीम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ काम करती है। यह किसी व्यक्ति परिवार या समाज की पार्टी नहीं है। पार्टी का सिस्टम बना हुआ है। यह

सब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। कई जगह चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े हैं और कई जगह बिना सीएम के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरे हैं।

कॉग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम नहीं हटेंगे...?

सूबे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलों को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने शिगूफा करार दिया है। सैलजा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना हुआ है, ऐसे में किसी परिवर्तन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राज्यों में इस तरह की सियासी शिगूफे उड़ते रहते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद यह संकेत दिया था कि संगठन में बदलाव होगा। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा शुरू हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को बदला जाएगा?सैलजा ने कहा कि प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है छग में भूपेश बघेल सरकार ने जिन मापदंडों को तय कर प्रदेश के लोगों के हित में काम किया है,संगठन उन्हीं योजनाओं को लेकर प्रदेश में काम कर रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे ही आधार बनाकर आगे बढ़ेगी और फिर सत्तासीन होगी।

और अब बस...

- छग के विवेकानंद एयरपोर्ट को निजी हाथों को सौंपने के निर्णय पर अंतिम मुहर लग गई है।
- सत्ताधारी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कुछ विधायकों द्वारा मंत्रियों को विस में घेरना चर्चा में रहा...
- विस सत्र के बाद कुछ एसपी, कलेक्टर, एएसपी, डीएसपी, पुलिस निरिक्षकों का तबादला होना तय है।
- हसदेव अरण्य में समस्त कोल ब्लाक रद्द करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है पर भूमि डायवर्सन अभी तक रद्द नहीं किया है...?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही -कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की केंद्र सरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से डरी हुई है इसीलिये संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिये पूरी भाजपा और केंद्र सरकार लामबंद होकर अलोकतांत्रिक आचरण पर उतर गयी है। भाजपा के आचरण और केंद्र के मंत्रियों के अतिवादी व्यवहार से साबित हो गया कि राहुल गांधी ने जो कहा था वह सच है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। विपक्षी दल के लोगों को संसद में बोलने से रोका जाता है। राहुल गांधी के ऊपर संसद में आधा दर्जन मंत्रियों ने आरोप लगाया लेकिन देश की प्रमुख विपक्षी दल के पूर्व अध्यक्ष को उनके ऊपर लगाये गये आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया जाता, जब वो बोलने उठते है तो माइक बंद कर दिया जाता है यह है भाजपा का फासीवादी चरित्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये राहुल गांधी यदि विदेश में सत्तारूढ़ दल के अतिवादी चरित्र के बारे में कुछ कहते है तो भाजपा को आपत्ति है लेकिन जब प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर आधा दर्जन बार देश की आलोचना करते है तो इसमें भाजपा को देशद्रोह नजर नहीं आता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे भाजपाई: धनंजय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से राजनीतिक नौटंकी करने वाले घड़ियाली आंसू बहाने वाले प्रदेश के भाजपा कब मोदी सरकार के रसोई गैस के बढ़ाए दाम के खिलाफ सड़कों पर उतर कर गरीब जनता की आवाज उठाएगी रसोई गैस के महंगे दामों का विरोध करेगी। मोदी सरकार की उज्वला योजना मोदी सरकार की मुनाफाखोरी अनियंत्रित महंगाई की भेंट चढ़ गई। मोदी सरकार के कुरीतियों के चलते मोदी सरकार की उज्जवला योजना असफल हो गई है । उज्जवला योजना के हितग्राही रसोई गैस की खाली टंकी में बैठकर धुआंदार चूल्हा से खाना बनाने मजबूर हैं।रसोई गैस के महंगे दाम के चलते प्रदेश के 35 लाख से अधिक उज्जवला योजना के हितग्राही सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं और पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक हितग्राही एक बार भी रसोई गैस के रिफिलिंग नहीं कराए हैं और 7 करोड़ हितग्राही 1 साल में एक ही रिफिलिंग ही करा पाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार देश भर की गृहणियों को रु. 410 में रसोई गैस की भरी सिलेंडर देती थी तब भाजपा के नेता रसोई गैस के दाम को महंगा बताकर विरोध करते थे आज नरेंद्र मोदी की सरकार रसोई गैस में मिलने वाले सब्सिडी को खत्म कर दी और उल्टा रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर दी।

सरकार युवाओं के साथ छल, कपट व अन्याय कर बेरोजगारी का मखौल उड़ा रही है-चौधरी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि सरकार के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों की गलत जानकारी देकर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवकों के साथ छल, कपट और अन्याय किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मंत्री उमेश पटेल को प्रदेश की युवा शक्ति से पहले क्षमा मांगनी चाहिए और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 13 हजार करोड़ का प्रावधान बतौर बेरोजगारी भत्ता करना चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि विधानसभा में प्रदेश के रोजगार मामलों के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5 प्रतिशत ही है लेकिन संख्या नहीं बता सकते। जबकि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार चाहने वाले 18.78 लाख युवकों ने पंजीयन कराया है। इन दोनों आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उमेश पटेल के दिए जवाब के अनुसार दशमलव 5% बेरोजगारी दर है इस दर से या तो छत्तीसगढ़ की आबादी तीन करोड़, नहीं बल्कि 36 करोड़ है या फिर बेरोजगारी दर के 0.5 प्रतिशत होने का दावा और लिखित उत्तर, दोनों झूठे है। इन झूठे आंकड़ों के आधार पर मंत्री पटेल और उनके विभाग ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया है, अन्याय किया है।

अडानी के हेराफेरी, लूट के षड़यंत्र और फर्जीवाड़े पर मोदी मौन क्यों? - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि हिंडेनबर्ग खुलासे के एक महिनें से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक ना कोई एफआईआर, ना किसी भी तरह की जांच का आदेश? आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में उजागर आर्थिक अनियमितता, मनी लॉड्रिंग, ब्लैक मनी और विदेशों में फर्जी सेल कंपनियां बनाकर किए जा रहे हैं फर्जीवाड़े पर भाजपा और मोदी सरकार की भी भागीदार है। अडानी से भाजपा को सपोर्ट मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है और इसीलिए अडानी को बचाने उसके फर्जीवाड़े पर मोदी सरकार पर्दा डाल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहा कि अडानी के घोटाले के कारण 120 मिलियन डॉलर अर्थात 10 लाख करोड़ से अधिक आम जनता के मेहनत का पैसा डूब गया है, देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर सरकारी बैंकों से अडानी को अनुपातहीन लोन किस के दबाव में दिया गया? षड्यंत्र उजागर होने के बाद भी एलआईसी का पैसा क्यों दबाव पूर्वक अडानी की कंपनी में लगवाया जा रहा है?

संवाद के माध्यम से बूथों को सशक्त करेगी भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के महती अभियान बूथ सशक्तिकरण की शुक्रवार को शुरुआत हुई। यह अभियान पूरे प्रदेश में आगामी 27 मार्च तक जारी रहेगा। विदित रहे, भाजपा का यह बूथ सशक्तिकरण अभियान देशभर में आहूत है। भाजपा प्रदेश महामंत्री व बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के संयोजक विजय शर्मा ने जानकारी दी कि बूथ सशक्तिकरण अभियान में प्रदेश में निवासरत भाजपा के राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेताओं पदाधिकारियों व सांसद विधायक सहित जनप्रतिनिधियों से लेकर मंडल इकाई तक के पदाधिकारी हरेक बूथ तक पहुंचेंगे। इस दौरान बूथ केंद्रों को सशक्त और सक्रिय करने के लिए कार्यकर्ताओं में दायित्वों का विभाजन किया जाएगा। इस पूरे अभियान में पार्टी के अल्पकालिक विस्तारक अपने–अपने बूथों में 10 दिन का पूरा समय देकर इस अभियान को पूरा करेंगे। प्रदेश के लगभग 4 हजार 4 सौ विस्तारकों ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों के साथ बूथों पर पहुंचकर अपनी कार्ययोजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन बूथों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का वाचन किया गया। विस्तारक इस पूरे अभियान में आम जनता से मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। इस दौरान विस्तारक कार्यकर्ता बूथों में निवासरत पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से ग्रहण मंत्रणा कर बुध की स्थिति की समीक्षा करेंगे।

मेडिकल कोर्स निजी यूनिवर्सिटी को देने का मामला पहुंचा कोट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पाठ्यक्रमों को निजी विश्वविद्यालयों के हाथों सौंपने की तैयारी के बीच नर्सिंग कालेज एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। शासन के फैसले के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में चला गया है। आशंका यह जताई जा रही है कि मेडिकल पाठ्यक्रम से जुड़ी मान्यता निजी विश्वविद्यालय हाथों में जाने से सीट की गुणवत्ता के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार आयुष विश्वविद्यालय लगातार पिछले 10 माह से चिकित्सा शिक्षा को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में अपना अभिमत संबंधित सारे विभागों और उच्च अधिकारियों को समय-समय पर दे रहा है। साथ ही इस ओर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा भी निजी विश्वविद्यालयों को ऐसे समय पर दी जा रही है जब प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के फर्जीवाड़े आम हैं। इस पर शासन की जांच रिपोर्ट यह बताती है कि निजी विश्वविद्यालय न कोई रिकार्ड रख रहे हैं और न ही शासन के कोई नियम को मान रहा है। नर्सिंग एसोसिएशन और आइएमए के पदाधिकारियों ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को चिकित्सा शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम देना और सरकारी विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना शासन की मंशा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने 10 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति

- **मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खेलों को बढ़ावा देने की पहल को मिली एक और बड़ी सफलता**
- **छत्तीसगढ़ में अब कुल 24 खेलो इंडिया सेंटर**

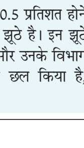

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत दस नए खेलो इंडिया लघु केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये दसों केन्द्र अलग-अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, कुश्ती, फुटबाल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केन्द्र की मंजूरी दी गई है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया केन्द्र की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आने वाले समय में ये खिलाड़ी न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह 'खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इण्डिया सेंटर प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल तथा सूरजपुर में फुटबॉल खेल की नए खेलो इंडिया लघु केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले जिला नारायणपुर में मलखम्भ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वालीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर में हॉकी एवं राजनांदगांव में हॉकी की खेलो इण्डिया लघु केन्द्र खोलने की कार्यवाही प्रगति पर है। अब तक पहले चरण के 7 जिलों में प्रत्येक जिले को लघु केन्द्र हेतु 7-7 लाख रूपए जारी किए जा चुके हैं। अन्य 7 स्वीकृत जिले बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन एवं सुकमा में फुटबॉल की राशि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार राज्य के 24 जिलों में 24 खेलो इंडिया लघु केंद्र के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। प्रत्येक खेल के स्थानीय सीनियर खिलाड़ियों को सेंटर से जोड़ा जाएगा, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में रखा जाएगा और कार्य करने के लिए मानदेय भी दी जाएगी। सभी खेलो इण्डिया सेंटर्स में बालक एवं बालिका खिलाड़ियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित की जाएगी। इन सेंटर्स को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.